

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 जनवरी, 1975

खण्ड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भुक्रवार, 10 जनवरी, 1975

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(9)1
वर्ष 1975-76 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)28

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 10 जनवरी, 1975

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा, विधान भवन, सैक्टर-1, चंडीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Question Hour.

B.K. Hospital

***1103. Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) the year in which the building of B.K. Hospital, Faridabad was constructed; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building for B.K. Hospital, Faridabad?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमति भारदा रानी):

(क) 1951

(ख) हां, परन्तु इस प्रस्ताव को निकट भविश्य में पूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।

श्री के.एन. गुलाटी: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदया ने अपने जवाब में फरमाया है कि यह बिल्डिंग 1951 में बनी थी। आप इस बिल्डिंग को बने हुए 25 साल हो गये हैं। 25 साल के बाद तो बिल्डिंग वर्थ यूज नहीं रहती है। तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि यदि वहां नयी बिल्डिंग नहीं बना सकते तो जो मौजूदा बिल्डिंग है उसकी रिपेयर करा देंगी?

श्रीमती भारदा रानी: माननीय अध्यक्ष महोदय वह बिल्डिंग बहुत अच्छी है। 25 साल पहले बनी बिल्डिंग बहुत पुरानी नहीं हो जाती। उससे भी पुरानी पुरानी बिल्डिंग पड़ी है। वह न कहीं से टपकती है और न ही टूड़ी फूटी है। कहीं कोई बात अगर होती है, तो उसकी रिपेयर की जाती रही है।

***1182. Shri Amar Singh:** Will the Minister for Development be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Bus Adda at Bawani Khera; Tehsil Head quarter, if so, when it is likely to be implemented?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): बवानी खेड़ा में बस अड्डा बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अमर सिंह: क्या यह हकीकत है कि जनरल मैनेजरने बवानी खोड़ा बस अड्डे के लिये जमीन एक्वायर करने के लिये लिख कर भेजा है ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: ऐसी कोई बात नहीं है ।

चौधरी फूल सिंह कटरिया: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि कोसली में, जो कि बहुत बड़ी मंडी है, कोई बस अड्डा बनाने का इरादा है ?

विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हमारा इरादा तो बहुत कुछ है लेकिन प्रायरिटी उन जगहों पर देते हैं जहां सब डिविजनल हैड क्वार्टर हो और यातायात के साधन अधिक हो ।

चौधरी बृज लाल: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि रानियां और एलनाबाद में कोई भौड्ज बनाने की योजना है ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: यह जवाब कर्नल साहब पहले ही दे चुके हैं । जैसे जैसे जरूरत है उस के मुताबिक प्रायरिटी देंगे । जहां पर जमीन फ्री देंगे वहां के लिये पहले टाप प्रायरिटी देंगे । उसमें एलनाबाद भी आयेगा तो उसको भी सोच लेंगे ।

श्री अमर सिंह: मिनिस्टर साहब ने अभी फरमाया है कि सब डिविजनल हैड क्वार्टर पर और तहसील हैड क्वार्टर पर अड्डे

बना रहे है। मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बवानी खेड़ा मे, जो कि तहसील हैड क्वार्टर है, जब तक परमानेंट बस अड्डा न बने, उस वक्त तक कोई टैम्परेरी अड्डा बनाने पर विचार करेंगे ?

कर्नल महा सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं वही जवाब फिर दोहराता हूं। पहले सब डिविजनल हैड क्वार्टर पर जहां पर जमीन एक्वायर कर चुके है, फिर तहसील हैड क्वार्टर पर जहां जमीन मिल चुकी है बस स्टैंडज बनाए जायेंगे। जहां जमीन मिल चुकी है बस स्टैंडज बनाये जायेंगे। जहां पर जमीन फ्री मिल जाती है वहां को टाप प्रायरिटी देते है।

चौधरी राम प्र ाद: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि रिवाड़ी के अन्दर खीरी, भाडास, टाकड़ी, प्राणपुर और खडीड़ा मे परमानेंट बस स्टैंड्स बनाने पर विचार करेंगे ?

कर्नल महा सिंह: अध्यक्ष महोदय, विचार तो बहुत कछ है कि लेकिन बजट इजाजत नही देता । जब बजट इजाजत देगा तो इन जगहो पर भी भौड्ज करेंगे ?

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कृपा करेंगे कि जहां नयी तहसील बनी है, एक साल से या छः महीने से जहां पर बरसात, धूप और सर्दी से बचने के लिये सवारियों के खड़े होने के लिये कोई भौड्ज बगैरह नही है, वहां पर टैम्परेरी तौर पर भौड्ज बनाने की योजना है ?

कर्नल महा सिंह: अध्यक्ष महोदय, बवानी खेड़ा तो अभी नयी तहसील बनी है। लेकिन हमारे पास अभी भी ऐसी जगह है जहां पर सब डिविजनल हैड क्वार्टर है, पुरानी तहसील है, आबादी भी ज्यादा है, यातायात के साधन भी है लेकिन वहां पर बस अड्डे नहीं हैं इसलिये पहले इनको प्रायरिटी देंगे। बवानी खेड़ा को भी जरूर प्रायरिटी देंगे उसके नम्बर के हिसाब से ।

Names of A,B and C class Municipal Committees

***1191 Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state the number and names of A,B and C Class Municipal Committees in the State which are at present under the direct control of the Administrators appointed by the State Government, separately together with the details of whole time and part time Administrators working in these municipalities?

State Minister for Cooperation and Local Government (Chaudhri Goverdhan Dass Chaudhan): There are at present 9 Class I and 19 Class II Municipal Committees in the State. The rest are known as Notified Area Committees which are 44 in number. There is no classification of municipal committees like A, B and C. All these committees are at present under the direct control of the Administrators/Presidents appointed by the State Government. The names of the Committees and the details of whole time and part time Administrators/Presidents appointed

thereto are given in the statement which is laid on the table of the House.

STATEMENT

Sr. No.	Name of the Committee	Officer appointed as Administrator/ President	Whether whole time or part time	Remarks
	Class 1			
1	Hisar	Sh. S.P. Lamba, HCS	Whole time	
2	Bhiwani	Sh. R.N. Singal, HCS	„	
3	Gurgaon	Sh. Prem Chand, HCS	„	He proceeded on 45 days earned leave and the S.D.O. (C), Gurgaon has taken over as Part time Administrator on 27.12.74
4	Rohtak	Smt. Kamla Chaudhry, HCS	„	

5	Ambala City	Sh. R.S. Chaudhry, HCS	,,	
6	Yamuna Nagar	Sh. V.P. Batra, HCS	Whole time	
7	Karnal	Sub Divisional Officer (C) Karnal	Part time	
8	Panipat	Sub Divisional Officer (C) Panipat	,,	
9	Sirsa	Executive Magistrate, Sirsa	,,	
	Class-II			
1	Kaithal	Sub Divisional Officer (C) Kaithal	Part time	
2	Kalka	Tehsildar Kalka	,,	
3	Charkhi Dadri	Sub Divisional Officer (C) Charkhi Dadri	,,	
4	Jagadhri	Sub Divisional Officer (C) Jagadhri	,,	

5	Shahbad	Sh. Hukum Singh Chehal, B.D.P.O.	Whole time	
6	Palwal	Sh. Bir Singh, B.D.P.O. Palwal	,,	
7	Fatehabad	Sub Divisional Officer (C) Fatehabad	Part time	
8	Jind	Sub Divisional Officer (C) Jind	,,	
9	Narwana	Sub Divisional Officer (C) Narwana	,,	
10	Gohana	G.A. to Deputy Commissioner Sonapat	,,	
11	Pehowa	Tehsildar, Guhla	,,	
12	Jhajjar	Sub Divisional Officer (C) Jhajjar	,,	
13	Sonapat	Extra Assistant Commissioner (U.T.) Sonapat	,,	

14	Bahadurgarh	Tehsildar, Bahadurgarh	„	
15	Thanesar	Tehsildar, Thanesar	„	
16	Mandi Dabwali	Sub Divisional Officer (C) Siirs	„	The orders for the appointment of Sh. B.C. Puri, B.D.P.O. as whole time Administrator has been issued but he has not joined so far. It has now been decided to appoint Sh. Chuni Lal Malhotra, Assistant, Haryana Civil Secretariat as whole time Administrator.
17	Hansi	Sh. Bihari Lal	Whole time	

		Gauba, Assistant, Haryana Civil Secretariat		
18	Narnaul	Sub Divisional Officer (C) Narnaul	Part time	
19	Rewari	Sub Divisional Officer (C) Rewari	„	
	Notification Area Committees			
1	Ferozepur Zhirka	Sub Divisional Officer (C) Ferozepur Zhirka	Part time	
2	Safidon	Naib Tehsildar Safido	„	
3	Beri	Tehsildar Jhajjar	„	
4	Hodal	Tehsildar Palwal	„	
5	Tohana	Tehsildar Hansi	„	
6	Jhakhal	Tehsildar	„	

		Fatehabad		
7	Uklana Mandi	Tehsildar Hansi	„	
8	Kalanwali	Naib Tehsildar Dabwali	„	
9	Loharu	Tehsildar Loharu	„	
10	Gharaunda	Tehsildar Karnal	„	
11	Chhachhrau li	Sub Divisional Officer (C) Jagadhri	„	
12	Buria	Sub Divisional Officer (C) Naraingarh	„	
13	Sadhaura	-do-	„	
14	Sohna	Sub Divisional Officer (C) Gurgaon	„	
15	Farrukhnag ar	Tehsildar, Gurgaon	„	
16	Hailey Mandi	G.A to Deputy Commissioner, Gurgaon	„	

17	pataudi	-do-	„	
18	Nuh	Sub Divisional Officer (C) Ferozpur Zhirka	„	
19	Uchana	Tehsildar, Narwana	„	
20	Meham	Naib tehsildar, Meham	„	
21	Mahenderga rh	Sub Divisional Officer (C) Mahendergarh	„	
22	Ateli	Tehsildar, Narnaul	Part time	
23	Kanina	Sub Divisional Officer (C) Mahendergarh	„	
24	Radaur	B.D.P.O., Ladwa	„	
25	Pundri	Tehsildar, Kaithal	„	It has been decided to appoint B.D.P.O. Pundri as President of

				<p>this Notified area Committee in addition to his own duties. Orders will issue on receipt of approval from the Development Department.</p>
26	Julana	Naib Tehsildar, Jind	„	
27	Bawal	Tehsildar, Rewari	„	
28	Ladwa	B.D.P.O., Kaithal	„	<p>Although orders of Sh. Tuhi Ram for appointment of whole time President Ladwa has been issued, he has not yet joined,</p>

29	Nilokheri	Sub Divisional Officer (C) Karnal	„	
30	naraingarh	Sub Divisional Officer (C) Naraingarh	„	
31	Ralway Workshop Jagadhri	Sub Divisional Officer (C) Jagadhri	„	
32	Ganaur	Sh. Sahu Ram	Whole time	
33	Tosham	Sh. Mange Ram	„	
34	Siwani	Sh. Kanwar Bhan	„	
35	Kalanaur	Sub Divisional Officer (C) Rohtak	Part time	
36	Maheshnaga r	Tehsildar, Ambala	„	
37	Pinjore	Town Administrator, H.M.T. Pinjore	„	
38	Ellenabad	Sh. Mahabir Pershad	Whole time	
39	Hassanpur	Sh. Din Dayal	„	

40	Bawani Khera	Sh. Ram Karan Dass	,,	
41	Narnaud	B.D.O. Narnaul	Part time	
42	Barara	Naib Tehsildar, Ambala	,,	
43	Sampla	B.D.P.O. Sampla		
44	Rania	Tehsildar, Sirsa		

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 44 कमेटीज की स्टेटमेंट दी जिन में से 15 कमेटीज पर होल टाईम एडमिनिस्ट्रेटर है और बाकी जगहों पर पार्ट टाईम ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाये हुए हैं, जिन में करनाल भी शामिल है। क्या कारण है कि ए क्लास म्यूनिसिपल कमेटीज में भी होल टाईम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाये गये हैं ?

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, कई जगहों पर पार्ट टाईम ऐडमिनिस्ट्रेटर है। ये बड़ी अच्छी प्रकार से काम कर रहे हैं। डिप्टी कमी नर्ज ने भी कहा है कि हमारा काम मौजूदा पार्ट टाईम ऐडमिनिस्ट्रेटर ठीक कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद हम ने भी गवर्नमेंट को लिखा है कि कम से कम जहां ए क्लास म्यूनिसिपल कमेटीज है वहां पर होल टाईम ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाने के लिये आफिसर दिये जाये।

ज्यों ही हमें आफिसर्ज मिल जायेंगे हम होल टाईम ऐडमिनिस्ट्रेटर लगा देंगे ।

चौधरी वृज लाल: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि रानिया जो नोटिफाइड एरिया डिकलेयर हो चुका है, वहां पर कोई काम नहीं चालू किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास गुप्त: वहां भीघ्र ही प्रबंध करेंगे ।

चौधरी फूल चंद कटारिया: क्या मंत्री झज्जर के अन्दर भी होल टाईम ऐडमिनिस्ट्रेटर लगायेंगे, क्योंकि वहां पर पार्ट टाईम ऐडमिनिस्ट्रेटर काफी दिनों से लगा है ?

श्री बनारसी दास गुप्त: जेसा कि अभी मै।ने अर्ज किया, ज्यो ही अफसर मिलेंगे हम होल टाईम ऐडमिनिस्ट्रेटर लगायेंगे । झज्जर के लिये भी प्रबंध कर रहे है ।

चौधरी ि।व राम वर्मा: नीलोखेड़ी काफी दिनों से नोटिफाइड एरिया कमेटी चली आ रही है, क्या वहां पर म्यूनिसिपल कमेटी बनाने का विचार है ?

श्री बनारसी दास गुप्त: नोटिफाइड एरिया कमेटी से म्यूनिसिपल कमेटी बनाने के लिये एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया हुआ है । जहां नोटिफाइड एरिया कमेटी की इंकम पांच लाख हो और आबादी 20 हजार या उससे अधिक हो तो उसे अपग्रेड किया जा सकता है ।

चौधरी पीर चंद: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिन कमेटीज में ऐडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं, क्या उन कमेटीज का इलैक्ट्रान कराने का कोई विचार है ?

श्री बनारसी दास गुप्त: ज्यों ही प्रबंध हो जायेगा, इलैक्ट्रान कराये जायेंगे।

राव अभय सिंह: क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि रिवाड़ी म्यूनिसिपल कमेटी में पहले होल टाईम ऐडमिनिस्ट्रेटर था लेकिन अब वहां पर पार्ट टाईम ऐडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया है। इसका क्या कारण है? क्या वहां होल टाईम ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाने का कोई प्रोजेक्ट है ?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि हम होल टाईम ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहते हैं लेकिन आफिसर्स की कमी है इसलिये हम नहीं लगा पाये हैं।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसे म्यूनिसिपल कमेटी में ऐडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं, उसी तरह नोटिफाइड एरिया कमेटीज में भी ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाने की कोई तजवीज है ?

श्री बनारसी दास गुप्त: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पार्ट टाईम लगे हुए हैं, किसी जगह प्रैजिडेंट लगे हुए हैं और किसी जगह पर होल टाईम ऐडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो म्यूनिसिपल कमेटीज मे एडमिनिस्ट्रेटर लगया रखे है, वे तीन साल तक काम करते रहेगे या उससे पहले वहां पर कोई चुनाव कराने की सम्भावना है ?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अभी इस बात का उत्तर दिया है कि चुनाव कराने की जो आवयक कार्यवाही है, वह हम करवा रहे है। जब वह पूरी हो जायेगी, हम इलैक्शन करा देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1141

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य सदन मे उपस्थित नहीं थे।

High School of Village Patirka

***1197. Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state—

1. whether there is any proposal under consideration of the Government take over high School of Village Patikra, Tehsil Narnaul; and
2. if so, the time by which the said proposal is likely to be implemented?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(ए) हां ।

(बी) इस बारे मे कोई निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है ।

Tubewell Connections

***1204. Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) the number of applications for electric connections to tubewells pending as on the 10th November, 1974, in Karnal and Kurukshetra Districts, separately;
- (b) the number of tubewells which were given electric connections during the period from 1st July, 1974 to 10th November, 1974, in Karnal and Kurukshetra Districts separately; and
- (c) the steps being taken to dispose of the remaining applications and the time by which electric connections are likely to be given to the applicants as referred to in part (a) above ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh):

- (a) The total number of pending applications for tubewell connections in district Karnal and kurukshetra as on 31-10-74 are as under:-

1. Karnal	3473	Karnal district is served by Karnal City, Karnal Suburban, Panipat City, Panipat Suburban and a part of Kurukshetra Division of Haryana State Electricity board.
2. Kurukshetra	3143	Kurukshetra district is served by Kaithal, Pehowa, major part of Kurukshetra and a part of Shahbad and Jagadhri Division of Haryana State Electricity Board.

(b) The total number of tubewell connections given during the period from 1st July to 31st October, 1974 are as under:--

1. Karnal 680
2. Kurukshetra 681

(c) The time taken to give the connections depends upon the submission of the test report by the consumer and availability of material.

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब अढ़ाई हजार के करीब करनाल में एप्लीके गन्ज पैडिंग पड़ी है और लगभग इतनी ही एप्लीकेशनज

कुरुक्षेत्र में बाकी पड़ी है तो आप ओर नई दरखास्तें लेने लग रहे हैं, ऐसा क्यों है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, दरखास्त लेने की बात तो उस वक्त चलती है, जब वह टैस्ट रिपोर्ट सबमिट करता है।

चौधरी राम लाल वधवा: मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 10 नवम्बर, 1974 से लेकर 31.12.1974 तक और कितनी एप्लीके शन्ज आयी और कितनी डिस्पोज आफ की गयी ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, इस पीरियड में कितनी नई एप्लीके शन्ज आयी है, वह तो मैं कह नहीं सकता, बहरलाल जितनी हमारे पास टैस्ट रिपोर्ट्स आती हैं उनके बेसिस पर मैटीरियल की बवेलेबिलटी को देखते हुए हम जल्दी से जल्दी कुनैव ान देने की कोशिश करते हैं।

चौधरी शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में टोटल नम्बर आफ पैडिंग एप्लीकेशन्ज करनाल में 3473 और कुरुक्षेत्र में 3143 बताया है जिनमें से करनाल में 680 और कुरुक्षेत्र में 681 कुनैव ानज दिये जा चुके हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाकी की टैस्ट रिपोर्ट नहीं आयी ? अगर नहीं आयी तो कितनी की नहीं आयी है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, मैं अक्टूबर 1974 की फिगरज दे रहा हूँ जो श्री मन्थस ओल्ड टैस्ट

रिपोर्ट्स आयी हुई है, करनाल डिस्ट्रिक्ट मे सिर्फ 785 है और कुरुक्षेत्र मे 767 है। सिक्स मन्थस ओल्ड टैस्ट रिपोर्टस 488 है और अब ये सिक्स मन्थस ओल्ड 288 है।

चौधरी वृज लाल: स्पीकर साहब, कल भी यह बात हाउस के सामने आई थी कि जिन्होंने अढ़ाई हजार रूपये जमा करवा दिये है और टैस्ट रिपोर्ट दे दी हुई है, उनको भी अभी तक कुनैकान नही मिला। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे लोगों को भी कुनैकान न मिलने का कारण क्या है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, मैंने यह अर्ज किया था कि जिन्होंने अढ़ाई हजार रूपया जमा करवाये है, उनको भी आपस मे प्रायोरिटी बनती है। जिसकी पहले टैस्ट रिपोर्ट मिलती है, उसको पहले कुनैकान मिलता है और जिसकल बाद मे मिलती है उसको बाद मे कुनैकान मिलता है।

चौधरी वृज लाल: स्पीकर साहब, ऐसे कई केसिज एक एक साल से पैडिंग पड़े है।.....(व्यवधान).....

चौधरी फूल सिंह कटारिया: स्पीकर साहब, मेरा हल्का बैकवर्ड एरिया करार दे रखा है और वहां पर अब भी दो दो साल के टयूबवैल कनैकानज पैडिंग पड़े है। क्या उनको कोई प्रयारिटी देने का विचार है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, यह तो सिर्फ कुरुक्षेत्र और करनाल डिस्ट्रिक्ट का सवाल है।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ऐस कितने केसिज हैं जिन में छः महीने से और एक साल से ज्यादा टैस्ट रिपोर्ट्स आयी हुई हैं और कुनैक गन्ज के लिये पैडिंग है।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: यह सवाल सिर्फ करनाल और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट्स के मुताल्लिक है।

श्री धजा राम: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि टैस्ट रिपोर्ट भी आ चुकी है और फिर भी थाउजैन्डस में ऐप्लीके गन्ज पैडिंग बतायी गयी है, उनको कुनैक गन्ज देने में डिले क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, मैंने तो टैस्ट रिपोर्ट्स थाउजैन्डज में नहीं बतायी, मैंने तो सौ में बतायी है।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि टैस्ट रिपोर्ट आने के बाद कितने दिनों के अन्दर कुनैक गन्ज दे दिया जाता है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, यह होता है कि जब टैस्ट रिपोर्ट आती है, तो एक लम्बी लिस्ट बनाते जाते हैं। ज्यो ही किसी का नम्बर आता है, उसको कुनैक गन्ज दे दिया जाता है। सब को बारी आने पर कुनैक गन्ज देते हैं। वर्मा साहब के मन में कहीं यह हो कि पिक एण्ड चूज की पोलिसी है, वह बिल्कुल नहीं है।

राव बंसी सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि डेढ़ डेढ़ साल हो गये हैं टैस्ट रिपोर्ट दिये हुए हैं, लेकिन उन्हें कुनैकान नहीं मिले। उनको कब तक कुनैकान दे देंगे ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: ये कहां की बात कर रहे हैं यह तो बता दें। उसके बाद मैं जो पोजीकान होगी, वह बता दूंगा।

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा में जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी टैस्ट रिपोर्ट्स हैं, उनका टोटल है 1322 जितनी टैस्ट रिपोर्ट्स तीन महीने से लेकर छः महीने तक पुरानी हैं, वे 2257 और तीन महीने तक की टैस्ट रिपोर्ट्स हैं 2502। कुनैकान देने दिये जाने का मेन कारण यह है कि आजकल सामान अवेलेबल नहीं है। इसलिये कुनैकान देने में देरी हो रही है।

चौधरी शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, कोठा बनाने के बाद, मोटर लगाने के बाद और बिजली का कुनैकान लेने के लिये बिल्कुल तैयार करने के बाद टैस्ट रिपोर्ट दी जाती है लेकिन फिर भी कुनैकान मिलने में सालों लग जाते हैं। उसके लिये किसान कितना ही रूपया खर्चा कर देता है। क्यों न ऐसा कायदा बना दिया जाये कि जब उसकी एप्लीकेकान को कुनैकान मिलने

का नम्बर आये तो उसको यह कह दिया जाये कि मोटर लगाओ, हम कुनैवान देंगे ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, अगर सब की ऐप्लीकेशन के साथ ही टैस्ट रिपोर्ट न ले तो फिर इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड इतने ज्यादा कुनैवान हनी दे सकेगा। मैं उनको यह बता दूँ कि हम उतनी ही टैस्ट रिपोर्ट्स इंगु करेंगे जितने कुनैवान्ज हम भी आ जाये और कुनैवान देने से पहले उन्हें यह लगे कि टैस्ट रिपोर्ट लाओं तो यह अच्छी बात नहीं होगी, इससे दिक्कत होगी।

श्री अजीत सिंह टिक्का: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन आदमियों ने कर्ज लेकर ट्यूबवैल लगवाने की कोशिश की है, अैस्ट रिपोर्ट दे दी है लेकिन उनको कुनैवान नहीं मिलता और उनकी किस्त ड्यू हो जाती है, कोआप्रटिव रिपार्टमेंट से मिलकर ऐसा करेंगे कि उसकी किस्त तब तक ड्यू न बने जब तक उनको कुनैवान न मिल जाये ?

श्री बनारसी दास गुप्त: ऐसा किया जाना संभव नहीं है।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: स्पीकर साहब, जो सवाल मैंने पहले पूछा था, भायद वह समझ नहीं सके। टैस्ट रिपोर्ट तो उस वक्त दी जाती है जब कोठा बनाकर और मोटर लगाकर कुनैवान लेने के लिये सब कुछ तैयार हो जाता है। इतना कुछ खर्च करने के बाद जमींदार सालों तक कुनैवान के लिये इंतजार करे, यह

ठीक नहीं लगता। क्या मंत्री महोदय इस बात पर चिार करेंगे कि टैस्ट रिपोर्ट आप उस वक्त मांगें जब उनको कुनैव न देने के लिये कहीं से बिजली उपलब्ध हो सके ?

श्री बनारसी दास गुप्त: जैसे मैंने अभी निवेदन किया है, हजारों एप्लीके न्ज सालों से हमारे पास पैडिंग है ही नहीं। मैंने पहले भी यह बताया है कि हमारे पास सारी स्टेट में 6 महीने से अधिक पुरानी टैस्ट रिपोर्ट्स केवल 1322 हैं। सालों तक टैस्ट रिपोर्ट्स पैडिंग पड़ी रहती हो, ऐसी कोई बात बात नहीं है।.....
(व्यवधान).....

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, इसके अलावा जो टैस्ट रिपोर्ट है, वह डिपार्टमेंट मांगता नहीं है। जो जमींदार अपने कुएं पर मोटर लगाता है वह तो खुद देकर जाता है।

श्री ओम प्रका ा गर्ग: स्पीकर साहब, जैसे कि कल मिनिस्टर साहब ने बताया था, अगर ऐसा कर दे कि कोई भी जमींदार जिसको टैस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, अपना मैटीरियल ले जाये और उस को जल्दी से जल्दी कुनैव न दे दिया जाये तो सारी की सारी एप्लीके न्ज डिस्पोज आफ हो सकती है ?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक प्र नके उत्तर में यह निवेदन किया था कि जो भी ट्यूबवैल का मालिक टैस्ट रिपोर्ट के साथ ही जो जरूरी सामान है वह खरीद

लाये और वह स्टेन्डर्ड का हो और उस सामान का रेट भी वह हो जो फिक्स किया हुआ है तो हम उसको कुनैक इन देने में प्रायरीटी देंगे ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या उसके पैसे बिलों में ऐडजस्ट करेंगे ?

श्री बनारसी दास गुप्त: जी हां, उसके पैसे बिलों में ऐडजस्ट करेंगे ।

श्री गौरी भांकर: मिनिस्टर साहब, ने अभी यह बताया है कि कोई जमींदार सामान खरीद लायें तो उसको प्रायरीटी देंगे । मैं यह समझता हूँ कि सामान खरीदने की बजाये अगर वह आपके महकमे के पास पैसे जमा करवा दे ताकि आपका महकमा ठीक सामान खरीद सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा ?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, केवल पैसे की दिक्कत नहीं है । यह ठीक है कि वैसे फंडज की भी कमी है लेकिन इतनी ज्यादा दिक्कत पैसे की नहीं जितनी दिक्कत सामान मिलने की है ।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कुनैक इन दिये जाते हैं, उसमें इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि बिजली पूरी अवेलेबल है या नहीं है ? मेरा ख्याल है कि कुनैक इन सिर्फ ऐप्लीके इन की बिना पर नहीं दिया जाना चाहिए । क्या सरकार बिजली की अवेलेबिलिटी

को ध्यान में रखकर यह निश्चित करती है कि इस साल में इतनी बिजली अवेलेबल है इसलिये इतने कुनैक गानज दिये जाये ?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय जितनी हमारे पास बिजली है, उसे इक्वली बांटकर दे देंगे। किसी को deprive हम क्यों करें ?

Deputy Commissioners and I.A.S. Officers

***1242. Ch. Chand Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether there is any Deputy Commissioner belonging to the Scheduled castes posted in any district of the State; and
- (b) the number of I.A.S. officers in the State, and the number amongs them of them of those belonging to Scheduled Castes?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

- (a) No.
- (b) The total number of I.A.S. officers at present borne on the State cadre is 105 and the number of officers belonging to Scheduled castes amongst them is 12. Of these the number of officers in the employ of the State and its Corporations etc. is 86 which includes 11 officers belonging to the Scheduled Castes.

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कि डिप्टी कमी नर लगाने के लिये सरकार किस ढंग से सोचती है?

चौधरी बंसी लाल : जिस आदमी को ठीक समझा जाता है लगा दिया जाता है ।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा सरकार ठीक या गलत सोचती है या केन्द्रीय सरकार सोचती है ?

चौधरी बंसी लाल : आई.ए.एस. कैडर के मेंबर सेंटर अलाट करना हे हमारी कोई 'say' नहीं है लेकिन डिप्टी कमि नर, डिप्टी सेक्रेटरी या किसी और पोस्ट पर लगाने का काम हरियाणा सरकार का है ।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 1968 से 1974 तक कितने हरिजन डिप्टी कमि नर लगे है ?

चौधरी बंसी लाल : यह फिगर तो मुझे याद नहीं है लेकिन कई डिप्टी कमि नर लगे है ।

चौधरी चांद राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कि भौड्यूल्ड कास्टस आई.ए.एस. डिप्टी सैक्रेट्री कितने है ?

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, चौधरी चांद राम ने तो सिर्फ डिप्टी सैक्रेट्रीज के नाम ही पूछे है मैं सब ही का ब्यौरा बता देता हूँ:

1	Sh. Kuttapan	Managing Director, Haryana Agro Industries
2	Sh. K.R. Punia	Registrar, Cooperative Societies.
3	Sh. Mohinder Singh Rathi	Deputy Secretray, Excise & Taxation,.
4	Sh. R.L. Sudhir	Managing Director, Haryana Financial Corporation.
5	Sh. Tarsem Lal	Director Consolidation & Records and Special Collector, Haryana.
6	Sh. T.D. Jogpal	Inquiry Officer Vigilence and also Jt. Excise & Taxation Commissioner, Haryana.

7	Sh. B.D. Dhalia	Registrar, Haryana Agricultural university.
8	Sh. Gian Chand	Joint Registrar, Cooperative Societies, Haryana.
9	Sh. Bhagwati Prashad	Sub Divisional Officer (C) Gohana and also Adminsitrator, Gohana Municipality
10	Sh. Chander Singh	Assistant Commissioner (Under Training) Jind.
11	Sh. Kartar Singh Goraya	Being allocated to Haryana amongst IAS Probationers (under training at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Mussoorie).

स्पीकर साहब, इनमे से बहुत सी पोस्टे ऐसी है, कम से कम आठ पोस्टें है, which are much more important than the Deputy Commissioner's post.

चौधरी चांद राम: क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के लोगों को डिप्टी कमि नर या डिप्टी सैक्रेट्री या सैक्रेट्री क्यो नी लगाया गया ?

चौधरी बंसी लाल: मैंने कह कि डिप्टी कमि नर भी काफी लगाते रहे है ओर डिप्टी सैक्रेट्री भी इनमे बहुत है और सैक्रेट्र के रैंक की जब किसी की टर्न आयेगी तो उसको लगाया जायेगा। बगैर टर्न के जूनियर को नही लगाया जाता।

चौधरी पीर चंद: क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1975-76 मे किसी भौड्यूल्ड कास्ट की डिप्टी कमि नर लगाने की टर्न आने वाली है ?

चौधरी बंसी लाल: डिप्टी कमि नर बाई रोटे इन नही लगाते।

चौधरी चांद राम: क्या मुख्य मंत्री महोदय इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि कमजोर वर्ग है यह जरूरी नही समझते कि किसी न किसी जगह भौड्यूल्ड कास्ट का डिप्टी कमि नर लगाया जाये ?

Ch. Bansi Lal: It is not necessary. For that all the Deputy Commissioners, which we have posted in the State, take care of the weaker sections.

चौधरी चांद राम: क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भौड्यूल्ड कास्ट के सारे आफिसर्ज को क्यों लाईन लगाया हुआ है ? डिप्टी कमि नर लगाने.....

चौधरी बंसी लाल: मेरी तरफ से तो ये अच्छी से अच्छी जगह लगाये हुये है। जैसे मिस्टर सुधीर मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंशियल कार्पोरे टन है। यहां हमे टा कमि नर रैंक का आदमी रहा है। तीन चार जगह इनमे से ऐसी है, जिन पर हमे टा कमि नर रैंक के आदमी रहे है। मिस्टर सुधीर डी.सी.' भी कई साल रहा है। कुटप्पन भी डी.सी. रहा है, पुनिया भी डी.सी. रहा है। डी.सी. भी कई रहे है। ऐसी बात नही है कोई डी.सी. न रहा हो।

श्री अमर सिंह: मुख्य मंत्री महोदय ने 11 या 12 भौड्यूल्ड कास्ट के आई.ए.एस आफिसर्ज के नाम बताए है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इनमे वाल्मीकि या धानक कितने है ?

चौधरी बंसी लाल: मेरे ख्याल मे एक भी नही है। अलबताा सकी बात को मुझे पता नही है। जहां तक मेरी नोलेज है, एक भी नही है।

चौधरी चांद राम: क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आई.ए.एस. का रिक्रूटमेंट कम्पीटी इन से थ्रू पब्लिक सर्विस कमी इन होता है ?

चौधरी बंसी लाल: यह तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। सभी जानते हैं कि आई.ए.एस. बाई कम्पीटी इन आते हैं।

B.K. Hospital Faridabad

***1104. Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

- (a) the total number of beds provided in the B.K. Hospital Faridabad at present;
- (b) whether the present building of the said Hospital is sufficient to accommodate the present number of beds; and
- (c) if not, the time by which this building is likely to be extended according to its bedded strength?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भारदा रानी):

- (क) 200 बिस्तर
- (ख) हां।
- (ग) प्र न नहीं उठता।

श्री के.एन. गुलाटी: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि गुड़गांव के अस्पताल में कितने बेडज हैं ?

श्रीमती भारदा रानी: दो सौ बिस्तर है।

श्री के.एन. गुलाटी: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि गुड़गांव के अस्पताल में 200 बैडज के मुकाबले में बी.के. अस्पताल में 200 बैडज की बिल्डिंग क्या कम नहीं है ?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, बी.के. अस्पताल और गुड़गांव का कोई मुकाबला नहीं है। फरीदाबाद गुड़गांव का हिस्सा है। गुड़गांव पूराजिला है जहां पहले 50 बैडज का अस्पताल था और बहुत ही बुरी कंडीशन में था, जहां एक चारपाई भी आराम से नहीं डाली जा सकती थी, अब वहां पर 200 बिस्तरों का अस्पताल बनाया गया है, जिसके लिये नई बिल्डिंग बनाई गई है। वैसे गुलाटी साहब बहुत विवकायत करते हैं कि फरीदाबाद में कुछ नहीं है। मैं फरीदाबाद के सारे में बताती हूँ कि यहाँ क्या क्या है। अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ में एक अस्पताल है जो साठ बिस्तरों का है और वह आल इंडिया मैडिकल इंस्टीच्यूट कोलैबोरेटिव में चल रहा है। वह, यद्यपि इनके क्षेत्र में नहीं है, परन्तु फरीदाबाद काम्पलैक्स में है। इसके अतिरिक्त एक एलोपैथिक सैक्टर सात में है और एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी ओल्ड फरीदाबाद में है। इसके अलावा वहाँ एक ई.एस.आई. का अस्पताल है, जो 92 बिस्तर का है, लेकिन जहाँ 100 बिस्तर का स्टाफ दिया हुआ है। वहाँ पर मैडीसन, सर्जरी, गैनेलोजी, ऐनीथीसिया, रेडियोलोजी, पैथोलोजी का इंतजाम है। इसके अतिरिक्त 9 ई.एस.आई. की डिस्पेंसरीज है।

फिर भी गुलाटी साहब परे गान रहते है कि फरीदाबाद मे कुछ नही है ।

चौधरी िव राम वर्मा: अभी मंत्री महोदया ने बताया है कि गुड़गांव के अस्पताल की कंडी गन बहुत खराब थी और चारपाई डालने की जगह भी बहुत कम थी। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि अब से पहल वहां एक एक चारपाई पर दो दो मरीज रखे जाते थे ? (हंसी)

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): एक चारपाई पर वर्मा जी और चौधरी रामलाल रखे जाते थे (हंसी)।

श्रीमती भारदा रानी: वहा 50 बिस्तरों का अस्पताल था और 50 ही मरीज रखे जाते थे ।

श्री के.एन. गुलाटी: क्या मंत्री महोदय के इल्म मे हे कि फरीदाबाद की आबादी सबसे ज्यादा है और वह लेबर एरिया है। मुझे मालूम है कि बी.के. अस्पताल मे 200 बैडज रखे गये है लेकिन क्या वह बिल्डिंग दो सौ बैडज के लिये नाकाफी नही है ?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग छारेटी होती तो दो सौ बिस्तरें कैसे आ सकते थे। दो सौ बिल्डिंग है, तभी इतने का इंतजाम है।

चौधरी िव राम वर्मा: गुलाटील साहब िकायत करते है कि फरीदाबाद मे मच्छर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से

वे बिमार हो जाते हैं। अगर उन मच्छरों को मरवा दिया जाये तो बीमारी भी नहीं फैलेगी और अस्पताल की आव यकता नहीं रहेगी।

श्रीमती भारदा रानी: गुलाटी साहब मरने ही नहीं देते।
(हंसी)

चौधरी पीर चंद: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि हसनगढ़ में जहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है डिसपेंसरी खोलने के लिये चिार करेंगी ?

श्रीमती भारदा रानी: वहाँ की कंडी ान को देखकर विचार कर लेंगे। वैसे यह प्र न फरीदाबाद और वह भी बी.के. अस्पताल के बारे में है।

Earth Work on Roads in Bawani Khera Constituency.

***1183.. Shri Amar Singh:** will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any rpposal under consideration of the Government to state earth work on the following roads to provide employment to the famine stricken people in Bawani Khera constituency in Bhiwani District—

1. Shiarwa to Guranpur;
2. Badon Rangran to Kanwari;
3. Nalwa to Atera;

4. Ratera to Tosham;
5. Rohnat to jmelpur;
6. Jamelpur to Bawani Khera;Bhuriana to Bhwani khera;
7. Baliali to Sui;
8. Paposa to Jamelpir; and
9. Dhamana to Tosham Via Ratera?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharm): No All of these roads are duplicate links, the constiructionof which is not being taken up at present.

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदया, अभी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब मे 'नो' कहा है। कई गांव अकाल ग्रस्त घोशित कर दिये है और वे सब अकाल के मुंह मे है और वहां पर लोगों के लिये कोई रोजगार नही है। क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सब चीजों को देखते हुए ऐसी गजहों पर कोई अर्थ वर्क भुरु करवाया जायेगा, जिससे लोगो को राहत मिल सके ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, भिवानी व बवानी खोड़ा के अन्दर 121 रोडज जो है, वे फ़ैमिन रिलीफ के अन्डर है, जिन मे से 26 रोडज पर काम चालू है। मीठाथल एप्रोच रोड और सिवाना यह दो रोडज जोकि चौधरी अमर सिंह जी के इलाके की है, वहां पर काम चालू है।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह जो छोटी छोटी लिंक्स है, जिन से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, क्या वहां पर थोड़ा बहुत काम भुरु करवाने की सरकार की कोई तजवीज है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: अध्यक्ष महोदय, सोलिंग हुआ पड़ा हो, कल्वर्टस हो, कम्पलीट मैटीरियल हो और स्टोन मैटीरियल पड़ा हुआ हो, फिर पार्ट मैटीरियल पड़ा हुआ हो, मिसिंग लिंक्स हो, इस तरह की प्रायोरिटीज है, जिनके हिसाब से हम काम करते हैं।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर झज्जर तहसील की सब तहसील नाहड़ में किन किन सड़कों पर काम चालू है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में ददनपुर से किरलोद, लाडपुर से ककरोला वाया करनोला, झज्जर गुड़गांव रोड से विलेज कुरानी और झज्जर बादली रोड से फ़ैजाबाद, इन चार सड़कों पर काम चालू है।

राव बंसी सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किन किन रोड़ज पर काम हो रहा है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुल 5 मेजर रोड़ज पर काम हो रहा है और 38

रोड़ज जो है, वे फ़ैमिल रिलीफ के अंडर ली है। अगर आनरेबल मेंबर चाहे तो मैं उनके नाम बता सकता हूँ।

राव बंसी सिंह: क्या मंत्री महोदय रोड़ज के नाम वहसील वाइज बताने का कश्ट करेंगे ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: डिस्ट्रिक्ट वाई नाम मेरे पास है। तहसील वाईज मेरे पास नाम नहीं है। इसके लिये मेंबर साहब अलग से नोटिस दे दे, हम बता देंगे।

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री साहब यह बतायेंगे कि अकाल पीड़ित इलाकों में जो दुर्भिक्ष पीड़ित लोग हैं, उनके लिये सरकार ने कोठ सहायता का प्रबंध किया हुआ है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, सारे महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, सारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में और झज्जर और रोहतक तहसील के एक हिस्से आदि में जहां पर यह ड्राट एरियाज है वहां पूरे इलाके में फ़ैमिन रिलीफ दिया जाता है।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, अभी इन्होंने कह कि बवानी खेड़ा में दो सड़कों मीठाथल और कूंगर सिवानापर काम चाजू है। लेकिन मेरी सूचना के मुताबिक इन गावों में कोई काम नहीं है और न ही वहां पर कोई अर्थ वर्क है। क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब यह फरमायेंगे कि इन इलाकों में कुछ रिलीफ देने का सरकार का विचार है या कोई काम भुरू करवाया जा रहा है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जिन इलाकों में ऐसी रोड़ज है, उनके अन्दर काम भुरू किया जा रहा है।

चौधरी पीर चंद: हिसर में 40 मील का एरिया कहत का एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। क्या सरकार की ओर से वहाँ पर कोई काम भुरू है ? अगर है, तो कौन कौन सी सड़कों के ऊपर काम भुरू है और वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: इस वक्त 16 रोड़ज पर काम चालू है। सोलिंग का काम दो सड़कों पर कम्पलीट हो चुका है जोकि हिसर से 7 किलोमीटर पर है और 400 के करीब आदमी वहाँ पर काम कर रहे हैं।

चौधरी िव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस वक्त सूखे का असर सारे हरियाणा में है और कुछ इलाकों में राहत का काम भी चल रहा है ? क्या नीलो खेड़ी के हल्का में भी सहायता कार्य आरम्भ करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: नीलोखेड़ी का एरिया इस कैटेगरी में फाल नहीं करता।

चौधरी चांद राम: जो सड़को के नाम चौधरी अमर सिंह के सवाल में दिये गये हैं, क्या इन इलाकों में कोई दुर्भिक्ष से

पीड़ित लोग है या नहीं ? अगर है, तो उन इलाको मे काम क्यों नहीं भुरु किया गया ओर नहीं किया गया, तो कब तक वहां पर काम भुरु करवा दिया जायेगा ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: जिन ड्राट हिट एरियाज मे आगे सड़के है, वहां दूसरी सड़के बनाने की गवर्नमेंट की कोई पालिसी नहीं है, वहां पर नहरों आदि का काम चालू है।

Persons Arrested under Section 107, 151, 148, 149 and 506 I.P.C.

***1214. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the district wise total number of persons arrested under section 107, 151, 148, 149 and 506 I.P.C. in the State during the period from April, 1968 to date separately; and

(b) the district wise total number of persons convicted, acquitted and let off out of those referred to in part (a) above separately?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भारदा रानी):

(क) और (ख) विधान सभा प्र न से संबंधित अपेक्षित सूचना का विवरण सदन मे प्रस्तुत है।

विवरण

(क) 1.4.68 से आज तक (30.12.74) की अवधि में निम्न धाराओं के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या:—

जिला	धारा 107 / 151 द.वि.सा.	धारा 148 / 149 भा.द.सा.	धारा 506 भा. द. सा.
करनाल	23738	169	110
रोहतक	19961	1566	173
हिसार	27412	117	1942
गुड़गांव	17459	585	351
जींद	12234	604	53
नारनौल	7243	273	80
भिवानी	9369	116	113
सोनीपत	3573	147	71
अम्बाला	10359	232	252
कुरुक्षेत्र	11949	147	283
जोड़	143297	3956	2978

(ख)

'क' भाग मे दिखाए गए व्यक्तियो मे से सजायाब अथवा पाबन्द किए गए व्यक्तियों की संख्या	'क' भाग मे दिखाए गए व्यक्तियो मे से बरी किए गए व्यक्तियों की संख्या
--	---

जिला	धारा 107 / 151 द.वि.स.	धारा 148 / 149 भा.द.सा.	धारा 506 भा. द. सा.	धारा 107 / 151 द.वि.स.	धारा 148 / 149 भा.द.सा.	धारा 506 भा. द. सा.
करनाल	1371	—	12	21338	56	51
रोहतक	3282	397	44	16250	1030	82
हिसार	3007	28	187	21068	76	872
गुड़गांव	1442	47	40	14700	354	140
जींद	2116	51	7	6294	310	19
नारनौल	588	24	7	6655	97	39
भिवानी	722	23	27	7305	70	40

सोनीपत	382	—	1	2038	3	—
अम्बाला	1090	14	10	9240	145	168
कुरुक्षेत्र	716	4	28	9892	78	109
जोड़	13762	588	369	114780	2219	1520

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदया ने अपने जवाब में बताया कि 1.4.68 से 30.12.74 तक 107, 151 के अन्दर 143297 आदमी पकड़े गये अर्थात् 148, 149 दफा के अन्दर 3956 व 506 दफा के अधीन 2978 आदमी गिरफ्तार किये गये हैं। क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगे कि इन में पालिटिकल क्षेत्र में कितने और दूसरे गवर्नमेंट कितने हैं ?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, वह अलग अलग नहीं निकाले गये हैं, क्योंकि सभी मुजरिम समझ कर पकड़े गये हैं।

चौधरी पीर चंद: क्या सरकार के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि मूल चंदराम के एक व्यक्ति को 26 नवम्बर को करनाल में गिरफ्तार किया गया और 27 नवम्बर को उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है ? इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, हमारे रिकार्ड मे जिस दिन गिरफ्तारी हुई है, उसी दिन कहा गया है।

चौधरी चांद राम: इस बारे मे मेरे पास कामरेड राम प्यारा का पत्र है।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): किस अच्छे आदमी का नाम ले दिया ?

चौधरी चांद राम: चौधरी साहब, जहां पर हम बैठे है, वह इस हाउस के सदस्य रहे है।

चौधरी बंसी लाल: रहा होगा, पागल हो गया है।

चौधरी चांद राम: जिस आदमी ने आजादी के लिये कुरबानियां की हो, उसे आप पागल कहते हो ?

चौधरी बंसी लाल: सारी उमर अच्छा रहा होगा, बुढ़ापे मे पागल हो जाये तो कोई क्या करे ?

चौधरी चांद राम: बुढ़ापा तो आप पर भी आयेगा चौधरी साहब।

Mr. Speaker: Please don't try to indulge in such things.

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि 26.11.74 को करनाल मे 78 आदमी गिरफ्तार किये गये और

उनकी गिरफ्तारी की तारीख 27.11.74 दिखाई गई है ? क्या यह फ़ैक्टस है ?

गृह मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल): बात तो यह है स्पीकर साहब, आप आनरेबल मੈंबर साहब को क्वै चन पढ़वा दीजिए, उसमे लिखा है 'the district wise total number of persons arrested' इससे यह क्वै चन कैसे पैदा होता है ?

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, जब यह सब जडिस है, तो अदालत देखेगी। अगर वह बेबुनियाद, बेगुनाह पकड़े गये है, तो अदालत रिहा कर देगी। स्पीकर साहब, अगर किसी ने कम्प्लेंट की हो, और अगर हमारे किसी अफसर की ज्यादती की हुई मिली हो तो उसे हम जरूर सजा देंगे।

चौधरी राम लाल वधवा: मंत्री महोदय ने अभी 107/151, 148/149 और 506 आई.पी.सी. के अंडर अरैस्ट किये हुए आदमियो की जो संख्या बताई है, उसमे बताया है कि 143297 जो 107/151 के तहत अरैस्ट हुए, उनमे से 13762 कनाक्ट या बाउंड डाउन हुए और 114780 जो है, वे एक्यूट हुए और इसी तहत 148/149 के तहत 3956 मे से 588 कनक्ट या आउंड डाउन हुए और 2219 एक्टिव हुए और 506 के तहत 2978 मे से 369 कनक्ट या आउंड डाउन किये हुये और 1520 एक्टिव हुए। तो क्या इससे जहा जाहिर नही होगा कि सरकार अंधा धुंध अन्याय करके लोगो को पकड़ती है ?

Mr. Speaker: It is a question but an expression of opinion. You please put a direct supplementary question.

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगी कि 1973-94 में 107/151 के कितने केसिज हाई कोर्ट में गये और वहां से ये आर्डर क्वैट हुए ?

श्री के.एल. पोसवाल: इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिए।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगी कि 1973-74 और 1974-75 में 107/151 के तहत कितने कितने आदमी पकड़े गए थे, 19431 बाउंड डाउन और 3861 का केस अभी चल रहा है।

श्रीमती भारदा रानी: 1973-74 में 25398 आदमी 107/151 के तहत पकड़े गये थे उनमें से 2106 डिस्चार्ज कर दिये गये थे, 19431 बाउंड डाउन और 3861 के केस अभी चल रहा है।

श्री के.एल. गुलाटी: स्पीकर साहब, इस दफ की हियरिंग जो है, वह एस.डी.एम. के पास होती है और एस.डी.एम. के पास एस.डी.ओ. सिविल का भी काम होता है, जिसकी वजह से उसके पास वर्क लोड ज्यादा हो जाता है। तो क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि एस.डी.ओ. सिविल और एस.डी.एम. की पोस्ट अलग अलग करने का विचार है ?

श्रीमती भारदा रानी: ऐसी कोई बात अभी विचाराधीन नहीं है।

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय के अल्म है कि जो 107/151 के तहत गिरफ्तार होते हैं उनकी जमानत के लिये एस. डी.ओ. जरूरी इनकार कर देता है कि पहले तहसीलदार से वैरीफिके इन कर लाओ, अगर है, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती भारदा रानी: यह तो जुडिगियरी का मामला है।

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय को पता है कि नरवाना तहसील में 7 आदमी गिरफ्तार हुए जिनकारपता तक हनी चला। क्या इसका पता किया जायेगा ?

Mr. Speaker: Order please. It is not a supplementary. How can this be a supplementary to the question, you just imagine yourself?

तारांकित प्र न संख्या 1142

यह प्र न पूछ नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।

**Bride and bridegroom Detained in Plice Station
Kanina**

***1173. Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Home be pleased to state—

- a) whether it is in the notice of the Government that a bride and a bridegroom while returning after marriage from village Rampura, District Mohindergarh by a car were taken to Police Station Kanini on 11-12-1974 in the evening; and
- b) whether it is a fact that the car and its driver were detained in the Police Custody, if so, the reasons for their detention?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) जी नहीं।

(ख) एक कार को मोटर वहिकल एक्ट तथा इसके तहत बनाये गये रूलज के प्रोविजन्ज की उलंघना के कारण कानूनी तौर पर पुलिस की सुपरदगी में रखा गया था। चालक को पुलिस हिरासत में नहीं लिया गया था।

राव दलीप सिंह: क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि कौन से रूल की वायलेंस की गई थी कि वह गाड़ी पकड़ी गई ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: वह जो गाड़ी थी, वह एक प्राइवेट गाड़ी थी, और उसको टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। तीन मील तक पुलिस ने उसका पीछा करके उसको पकड़ा।

राव दलीप सिंह: क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि इस गाड़ी के अंदर जो दुल्हा दुल्हन थे, क्या उनको भी जेल में रखा गया ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: ऐसी कोई बात नहीं हुई। सवारियां तो कनीना में ही उतर गई थी, और सिर्फ गाड़ी को ही ले जाया गया था।

Canals water for Agriculture Purposes

***1205. Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- a) the quantity of water available in the canals in the State for agricultural purposes at present;
- b) the quantity of canal water required for agricultural purposes at present together with the quantity of water being supplied for this purpose; and
- c) the measures adopted to meet the shortage of water and the time by which full supply of water is expected to be made?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohindr Singh Chatta):

- a) The quantity of water available in the canals in the State for agricultural purposes at present (as on 1-1-75) is as under—

(i) Western Jamuna Canal	2253 Cusecs
--------------------------	-------------

- (ii) Bhakra Canal 2961 Cusecs
- (iii) Gurgaon Canal 300 Cusecs

b) The quantity of canal water required for agricultural purposes at present (for month of January) together with the quantity of water being supplied for this purpose is—

	Quantity of water required	Quantity of water supplied (1-1-75)
(i) Western Jamuna Canal	4550 Cs.	2253 Cs.
	4189 Cs.	2961 Cs.
ii) Bhakra Canal	420 Cs.	300 Cs.
ii) Gurgaon Canal		

c) measures adopted to meet the existing shortage are—

- (i) Conservation of water through lining of canals.
- (ii) Utilisation of ground through augmentation tubewells.
- (iii) Participation in the construction of Beas Project.

The time by which full supplies of water would be available cannot be indicated at present.

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय की नोलेज में है कि पानी को बढ़ाने का जो बेस्ट तरीका है, वह सिर्फ सही है कि हमारी छोटी या बड़ी नदियां बहती हैं, जैसे घग्गर है, मारकंडा है,

या जमुना है, उनके ऊपर बांध बनाए जाये, क्या ऐसी कोई तजवीज है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: घग्गर के बारे में पहली बात तो यह है कि वह इंटर स्टेट नदी है और दूसरे इस पर बांध बनाने के लिये 30-40 करोड़ रूपया चाहिए। जो छोटी छोटी नदियां चलती हैं, हम उनको कनवर्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों सी. एम. साहब ने भी हुक्म दिया था कि स्टेट की प्लान बनाओ, जो छोटी छोटी नदियां चलती हैं, उनको कनवर्ट करो, ताकि जो पानी जमुना की तरफ बहता है, उसको ज्यादा से ज्यादा मोड़ा जाये। यह कोर्न प्लान हम कर रहे हैं।

मलिक सतराम दास बतरा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो 26 स्परिकलिंगपम्प आपने इम्पोर्ट किये हैं, नको कौन से बैंक में लगाएंगे या उन्हें कौन सी कृषि परियोजना में लगा रहे हैं ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, यह सवाल अवेलेबिलिटी आफ वाटर का है। इस सप्लीमेंटरी का इससे ताल्लुक नहीं है।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, मैंने घग्गर के बारे में पूछा था?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब मैंने अभी बताया कि वह इंटर स्टेट नदी है।

Chef Minister (Ch. Bansi Lal): that is under consideration of the Government of India.

चौधरी बृज लाल: क्या मंत्री महोदय की नालेज में यह बात है कि मतेरे हल्के में 10-15 गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी है और मौजगत में एक नहर निकाली जानी थी ? सी.एस. साहब और चीफ इंजीनियर भी वहां गये थे और सी.एस. साहब ने कहा था यह नहर जरूर बनेगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वह कब तक बनेगी ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: अगर सी.एम. साहब कह कर आये थे, तो जरूर बनेगी।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: मंत्री महोदय ने अभी बताया कि सरकार जितने पाली की लगभग जरूरत समझती है उतना मिल रहा है। मेरा ख्याल है कि उसे आधा या उससे भी कम मिल रहा है। तो यह पानी कब तक पूरा मिलेगा, क्योंकि खेती का नुकसान हो रहा है ? सरकार इसके बारे में जल्दी क्यों नहीं सोच रही है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, जितना यह सरकार सोच रही है उतना वह सरकार आठ महीने तक सोई रही है। (हंसी)

श्री प्रेम सुख दास: ओटू लेक में सिल्टिंग बहुत ज्यादा हो गई है, क्या उसकी डिसिल्टिंग करवाने की कोशिश करेंगे ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: जरूर, यह विचार में है।

Reservations in Class I and II Posts

***1243. Ch. Chand Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state—

- a) whether the Haryana Government has received any orders from the Government of India regarding reservation in promotions in Class I and II posts for members of the Scheduled Castes and backward Classes, if so, a copy thereof, be laid on the Table of the House; and
- b) the action, if any, taken thereon?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

- a) No.
- b) The question does not arise.

चौधरी चांद राम: क्या कभी मुख्य मंत्री जी ने हाउस में यह आवासन दिलाया था कि भौडयूल्ड कास्ट के लिये प्रमोशन में रिजर्वेशन की जायेगी ?

चौधरी बंसी लाल: मुझे याद नहीं, अगर आवासन दिया गया होगा, तो वह हाउस में रिकार्ड पर होगा।

चौधरी चांद राम: मुख्य मंत्री जी ने 'नो' में जवाब दिया है, क्या उनके पास सुप्रीम कोर्ट का डिजीजन आया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: यह जो उन्होंने 'नो' में जवाब दिया है, वह सैन्ट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन्स के बारे में है।

चौधरी चांद राम: क्या अगर उनको इंस्ट्रक् टान्ज की कापी सप्लाई की जाये, तो विचार करेंगे ?

चौधरी बंसी लाल: वह भी जब आएगी, देख लेंगे कि क्या करेंगे। (हंसी)

वर्ष 1975-76 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं यहां सदन में परसो अर्ज कर रहा था बजट पर बोलते हुए कि हमारा देहातों का देहात है, किसानों का देहात है, और यह कृषि प्रधान देहात है और हमारा यह प्रदेश इस देहात में खेती प्रधान है। इसके अन्दर 80 फीसदी लोग देहात में रहते हैं और 80 फीसदी का दारोमदार खेती पर है। इस बारे में मैं आपका ध्यान ग्रोमोर फूड इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूँ और उस रिपोर्ट की चार पांच लाईने पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। वे हैं:-

“Human problem facing India as Welfare State—
India, as a Welfare State is thus facing one of the world’s most difficult human problems. For, the betterment of rural life eighty per cent of the population of India lives in villages is essentially a human problem. This is the tremendous task of creating among sixty million families living in villages “a burning desire to change their old time outlook and arouse

enthusiasm in them for new knowledge and new ways of life” a will to live better”-----On the economic side, the basic fact is the enormous volume of unemployment and disguised unemployment that exists in agriculture owing to the pressure of a steadily increasing population on the soil. The facts relating to this are well known but will bear restatement. Owing to seasonal conditions, work in agriculture is possible only for portion of the year.”

तो आप देखें कि हमारे देश की मेजर पापुलेशन जो देहात में रहती है, उसके रोजगार की क्या हालत है? देहात में किसान को साल में तीन महीने ही काम करने को मिलता है और बाकी 9 महीने वह खुद भी बेकार रहता है और जब वह बेकार होता है तो जिन लोगों का सारा दारोमदार किसान पर है, खेती पर है और खेतों में मजदूरी करके रोटी कमाने से जिनका गुजारा चलता है, वह तो बेकार खुदबखुद ही हो गये। मेरे कहने का मतलब यह है कि देहात को सुधारने के लिये और किसान को प्रोत्साहन देने के लिये जरूरी है कि किसान को प्रोत्साहन देने के लिये जरूरी है कि किसान को ज्यादा पानी मिले और पानी के साथ साथ दूसरी सुविधाएं जो पैदावार बढ़ाने के लिये जरूरी होती हैं दी जायें। यह मैं मानता हूँ कि किसान की हालत कुछ सुधरनी है और उसे काफी सुविधाएँ देने का प्रयत्न किया गया है। आज से 20-25 साल पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि किसान की यह हालत थी कि किसान की दो सालों की कमाई हर साल गांव के सेठ साहूकार के हवाले हो जाती थी। उस में अब तबदीली आई

है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारा किसान अनथक मेहनत करने वाला है, उसको अगर साधन जुटा दिये जाये तो वह अपने पांव पर खड़ा हो सकता है और पैदावार के लिहाज से दे आगे ले जा सकता है। यह ठीक है कि हरियाणा में किसान को पैदावार बढ़ाने के लिये साधन जुटाने की काफी कोशिश की गई है। जहां तक पानी इरीगेशन के लिये देने की बात है, उस बारे में मैं हरियाणा, 1973 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस मैं लिखा है:—

“Water is the prime requisite of farming. The higher priority has, accordingly, been given for increasing irrigation through major and minor irrigation works. The number of tubewells and pumping sets which stood at a little over one lakh at the end of 1970-71 is expected to be 1.38 lakh by the end of the current year.”

इस हाउस में काफी आंकड़े दोनों तरफ से पेश किये गये हैं और हमारे एक साथी ने उन को कुछ को चैलेंज भी किया है लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ और प्लान पर 9 लाख 70 हजार रूपया रखा था। इस साल इसको अधिक बढ़ाया है। इसी तरह नैवीगेशन और ड्रेनेज पर भी पैसा बढ़ाया है। बजट वाल्यूम 2 के पेज 25 पर नान ल्पाल स्कीम के तहत जिसमें फलड कंट्रोल, नैवीगेशन और ड्रेनेज आती है, 17 करोड़, 42 लाख, 39 हजार, 330 रूपया और प्लान के तहत 21 करोड़, 73 हजार 300 रूपया खर्च करने का फैसला किया है। मैं समझता

हूँ कि यह सराहनीय कदम है क्योंकि पानी के बगैर पैदावार बढ़ नहीं सकती, इस बात को बहुत सारे भाई कहेंगे। स्पीकर साहब आपके जरिये सरकार से निवेदन करूंगा कि पानी के मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। रीजनल इम्बैलेंसिज को खत्म करने का सरकार ने फैसला किया है लेकिन वह अभी तक कायम है। जिला महेन्द्रगढ़ और भिवानी के टिब्बे आसमान को छूते नजर आते हैं। मेरे कई भाई करनाल और कुरुक्षेत्र का मुकाबला भिवानी डिस्ट्रिक्ट से करते हैं। अगर कुरुक्षेत्र में, करनाल में बहुत अच्छी बारिश हो और फसल लहलहा रही हो तो भिवानी में उस वक़्त भी अकाल होता है क्योंकि उस इलाके में कोई साधन नहीं है जिनके ऊपर वहाँ के लोग पैदावार करके निर्वाह कर सकें। (घंटी) स्पीकर साहब, मैंने तो अभी भुआ ही किया है मुकिल से पांच मिनट ही बोला हूँ जुई लिफ्ट रीगेन की लाईन 100 किलोमीटर लम्बी है और 7 गडी नल पम्पिंग स्टेन है। 1972-73 में लगभग 44 हजार एकड़ जमीन को इस नहर ने पानी दिया है और ऐसे खेतों को पानी दिया है जहाँ अन्न पैदा ही नहीं होता था, टिब्बे मिलते थे। वह धरती ऐसी थी जिसमें पक्षी प्यासे मरते थे। ऐसे एरिये में जुई लिफ्ट इरीगेन से पानी मिलता है। इसी तरह इंदिरा गांधी कैनल है। बी.एन. चक्रवर्ती फीडर 135 मील लम्बी है, 8.75 करोड़ रुपये की लागत से बनी है और 1 लाख 93 हजार 800 एकड़ में पानी देगी। इन नहरों के कम्प्लीट होने के बाद भी मैं समझता हूँ कि भिवानी और महेन्द्रगढ़ का इलाका कुरुक्षेत्र और करनाल के इलाके से 25 साल पीछे रहेगा क्योंकि

जब तक इनके टिब्बे वहां खत्म नहीं होंगे तब तक हम यह एक डिस्पैरिटी महसूस करेंगे। यहां के लोग बहुत अकालों का मुकाबला करते आये हैं। अब उनका हौसला बढ़ गया है, और समझते हैं कि कम से कम अपने पांवों पर खड़े हो सकेंगे, अपने बच्चों के लिये पैदावार कर सकेंगे। यह आंकड़ों की बात नहीं है, तारीफ की बात नहीं है, यह तो साक्षात बात है जो सरकार ने उस इलाके को सम्भालने के लिये पानी का इंतजाम किया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और इरीगेशन का आपस, में बहुत अधिक संबंध है इसीलिये ये दोनों महकमे एक ही मिनिस्टर के पास आये हैं। इन दोनों का तालमेल इतना अच्छा है ताकि किसान को पानी, बीज और दूसरी सुविधाएं एकदम मिले। इस तालमेल से किसान की पैदावार ज्यादा बढ़ सकती है। हरियाणा प्रान्त में गेहूं की पैदावार 68 परसेंट से किसान की पैदावार ज्यादा बढ़ी है और चावल की पैदावार 86.7 परसेंट बढ़ी है। 1968 में अब तक के मुकाबले में। स्पीकर साहब, इलैक्ट्रिसिटी का होना आवयक है। एग्रीकल्चर के लिये इलैक्ट्रिसिटी ऐसा साधन है जिस के वगैर आज पैदावार नहीं बढ़ सकती। आठ साल पहले जब मैं ज्वायंट पंजाब में एम.एल.ए. था उस वक्त हम तड़पते थे कि बिजली दो लेकिन दस दस हजार की आबादी वाले गांव में बिजली उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आज हम गौरव से कहते हैं कि हर गांव में बिजली है, यह आंकड़ों की बात नहीं है, यह हकीकत है, हर गांव में बिजली है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बिजली जहां एग्रीकल्चर प्राइवेट में के लिये इस्तेमाल की जा रही है वहां दस्तकारी के

भाओवे मे भी नुमायां हुई है। 900 के करीब इंडस्ट्रीयल युनिटस लगे है जिन पर 20 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है लेकिन फिर भी दस्तकारी की तरक्की की और ज्यादा जरूरत है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि यह एक महान दे आ है, देहातों का दे आ है, एग्रीकल्चर परनिर्भर करने वाला दे आ है, खेती पर निर्भर करने वाला दे आ है लेकिन इसके साथ साथ जब तक दे आ मे दस्तकारी की तरक्की नहीं होगी, लोगो को काम नहीं मिलेगा, यह हकीकत हैं स्पीकर साहब, देहात के लोग जहां एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते है वहां बहुत सारी जनता दस्तकारी पर भी डिपेंड करती है। अपना काम खत्म करेन के बाद किसान 9 महीने बड़ी बेताबी से गुजारता है। इस बेकार टाइम मे वह दस्तकारी का काम कर सकता है। ऐसे एरियाज मे, ऐसे देहातों मे जब तक दस्तकारी नहीं दी जायेगी तब तक हमें रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता। सब को काम देने के लिये छोटी छोटी दस्तकारियां देहातों मे देनी चाहिए जैसे नवार बनाना, दरियां बनाना वगैरा कई इस किस्म की दस्तकारिया है जिन से दे आ की प्रोडक इन बढ़ सकती हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटस की फैक्ट्रियां खोलनी चाहिए। इसमे लोगो को काम मिलेगा और काम करने से वे अपने पावों पर खेडे हो सकेगें। स्पीकर साहब, मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूं। इसके अतिरिक्त जहा। राईजिंग आफ प्राइसिज की प्रौब्लम है, अन उम्पलायमेंट की प्रौब्लीम है। जहां इंक्रीज आफ पापुले इन की प्राब्लम हैं, वहां भाडयूल्ड कास्ट की भी एक बड़ी प्रौब्लम है। हिनदुस्तान के सामेने एक हरिजन प्रौब्लम है, इसको हल करने के लिये प्रयत्न करने

चाहिये। जहां तक हरियाणा में इनकी तरक्की का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ, बहुत नुमायां कदम उठाये गये हैं। उनको साधन जुटाने के लिये और आगे लाने के लिये। सुबह ही एक सवाल था जिसके जवाब में बताया गया कि हरियाणा के अन्दर 12 आई.ए.एस. ऑफिसर, 11 एच.सी.एस. ऑफिसर और करीब 7-8 आई.पी.एस. ऑफिसर हैं। यह ठीक है कि एक जमाना था जब संत रविदास और संत कबीर के जमाने में अनटचेबिलिटी इतनी थी कि पतित को, दलित को छोड़े बांध कर गांव में आना पड़ता था। आज जमाना वह नहीं है लेकिन जहां तक डिसपैरिटी दूर होनी चाहिये, जहां तक इकॉनॉमिकली हम बराबर आने चाहिए उस स्तर पर हम सोर दे 1 में अभी तक नहीं आ सके हैं। यह ठीक है कि हरियाणा सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है कि इनको रोजगार दिया जाये। स्पीकर साहब, हाउस में दौलता साहब और मेरे दूसरे कुछेक भाई तरह तरह के प्वायंट उठाते हैं और कहते हैं कि हरिजन जमीन छिनेंगे मैं कहता हूँ कि इस तरह की भावना रखने वाले आदमी और वे हरिजन लीडर जमीन भी जो जमीन के नाम लेकर के तरह तरह की बातें करते हैं, बड़ी गलत विचारधारा लोगों में फैलाते हैं हरिजन किसी की जमीन नहीं लेना चाहता। हरिजन वह जमीन लेना चाहते हैं जो सरकार के पास इवैक्यू लैंड के रूप में फालतू पड़ी है, जो पैकेज डील में सेंट्रल गवर्नमेंट और ज्वायंट पंजाब से मिली थी, जो लैंड लार्डज के पास सरप्लस बचती है। इस तरह की बिटरनेस क्रिएट करके, रौला मचा करके ये लोग गाड़ी के दो पहियों में गड़बड़ फैलाते हैं। यह दे 1 के हित में नहीं है। स्पीकर

साहब, किसान और मजदूर देहात में रहते हैं। ये गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। गाड़ी के दो पहियों में से यदि किसी एक का फाचरा निकल जाये तो गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिये गांव के इन दो पहियों के ठीक चलने के लिये यह जरूरी है कि इनमें तालमेल हो और यह तालमेल कब होगा, स्पीकर साहब, जब ये बिटरनैस की भावना फैलाने वाले लोग न हों। किसान चाहता है हरिजन की मदद और हरिजन चाहता है कि किसान के खेत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। गड़बड़ किस बात की? गड़बड़ तो अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग फैलाते हैं। ये इनका तालमेल बिगाड़ कर अपना उल्लू सीधा करते हैं और इस तरह अपने प्रदे 1 और दे 1 को नुकसान पहुंचाते हैं। स्पीकर साहब, हमारी हरियाणा की सरकार बड़ी मजबूत है और इसने कई मामलों में सारे हिन्दुस्तान में पहल की है। मैं इससे आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से इसने ट्रांसपोर्ट ने नेलाइजे 1न और टोटल इलैक्ट्रिके 1न के मामले में पहल की है उसी तरह से रिजर्वे 1न को खत्म करने के मामले में भी पहल करे। मैं नहीं चाहता कि रिजर्वे 1न हमें 11 के लिये कायम रहे। यह लानत पट्टा हमें 11 के लिये हटना चाहिए ब 1र्ते कि सरकार पहले क्रे 1 प्रोग्राम बना करके हरिजनों को इकॉनोमिकली हालत अच्छी बनादे। स्पीकर साहब, अठारह लाख के करीब हरियाणा में हरिजन पापुले 1न हैं। ये लगभग 5-6 हजार कुनबे बनते हैं 1और इनमें से बहुत थोड़े कुनबे ऐसे होंगे जिन्हें चौधरी चांद राम जी जमीन पर बसाना चाहते हैं वरना बाकी के कुनबे काम चाहते हैं। हम काम

दिलाने के हक में है। मुझे इस बात को जानकर बड़ी खुशी हुई कि सरकार एक बीविंग स्पीनिंग मिल हांसी में दे रही है। उस पर तीन करोड़ रुपये लगाये जा रहे हैं। यह बड़ा सराहनीय काम है। इसी तरह मुकर्रर कर दी जाये और एक साल के अन्दर अन्दर ये जो 6-7 हजार कुनबे हैं इनमें से कुछेक को तो जमीन दे दे जो जमीन चाहते हैं उनको रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार दे दे, जो दस्तकारी चाहते हैं उनको दस्तकारी में लगवा दे, चाहे इस पर पांच करोड़ रुपया खर्च करना पड़े, दो करोड़ रुपया खर्च करना पड़े, कर दिया जाये। तो मैं सबसे पहला भाख्स हूंगा हरियाणा में जो यह रिकोमेंड करेगा कि हरियाणा में रिजर्वे लैंड की कोई जरूरत नहीं है।

Mr. Speaker: Please wind up your speech.

श्री अमर सिंह: मैं अभी वाइन्ड अप कर रहा हूँ। स्पीकर साहब, अब मैं एक और बात के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ वह है इन्टरसी अनटचेबिलिटी की बात है। स्पीकर साहब, इन्टरसी अनटचेबिलिटी सिर्फ हरियाणा ही में नहीं बल्कि सारे देश में है। इसको कम से कम अपने हरियाणा में दूर करने के लिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। हरियाणा में गांव के अन्दर आम तौर पर वाल्मीकि, धानक, चमार, इन तीन बिरादरियों के लोग बसते हैं। कुछ खटीक, सांसी और बोरिया बिरादरी के लोग भी रहते हैं लेकिन इनकी तादाद बहुत थोड़ी होती है। (विघ्न) वैसे तो कोई 63-64 कम्युनिटीज हैं लेकिन मेजर कम्युनिटीज यही हैं। खैर,

स्पीकर साहब, मैं यह कहने जा रहा था कि सरकार जो चोपाल के लिये पैसा देती है। वह सिर्फ वहीं दिया जाये जहां गांव के सारे हरिजन ज्वायंटली प्रस्ताव पास करके दे। अभी तक तो यह प्रैक्टिस चली आ रही है कि जब चमार दरख्वास्त देते हैं तो दस हजार रूपये उनको दे देते हैं, जब वाल्मीकि चाहते हैं तो दस हजार रूपये उनको दे देते हैं और जब खटीक चाहते हैं तो दस हजार रूपया उनको दे देते हैं। मैं तो कहता हूं कि यह इंटरसी अनटचेबिलिटी हम क्यों पैदा करें ? अनटचेबिलिटी, स्पीकर साहब, तभी खत्म हो सकती है जब पहले इंटरसी अनटचेबिलिटी दूर हो। जब इंटरसी अनटचेबिलिटी खत्म हो जाये तभी हम सही मायने में दूसरों को मजबूर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह छुआछुत दूर हो। स्पीकर साहब, महात्मा बुद्ध, कबीर, रविदास और पूज्य महात्मा गांधी, ये सारे कुर्बानी देकर चले गये लेकिन अनटचेबिलिटी कायम है। यह ठीक है कि अनटचेबिलिटी जिस तरह मैंने पहले कहा, उस स्तर पर नहीं है जिस पर संत कबीर और रविदास के जमाने में थी। लेकिन देहात में जो रहते हैं वे इस बात को जानते हैं कि आज भी वहां अनटचेबिलिटी है। आज हालत यह है कि इकॉनोमिकली जिसकी हालत अच्छी बन जाती है उससे तो यह दूर हो जाती है लेकिन जो गरीब है उसके यह चिपटी रहती है। इसलिये यह जरूरी है कि देहात में हम इन लोगों की इकॉनोमिक हालत बेहतर बनाने के लिये साधन जुटाये।

स्पीकर साहब, जो फ़ैमिन हिट एरियाज है उनके बारे में आनरेबल चीफ़ मिनिस्टर साहब सारे इलाके में यह कह कर आये थे कि रोड़ज पर काम करने वाले आदमियों को तीन मील से दूर नहीं जाना पड़ेगा, सबको तीन मील के अन्दर अन्दर काम मिलेगा। आई.पी.एम. साहब ने भी यही बात दोहराई लेकिन आज एक प्रश्न के जवाब में रैवेन्यू मिनिस्टर ने यह बताया कि किसी गांव में काम भुरू नहीं हो सका। सारी तहसील भिवानी खेड़ा में कोई 70-75 गांव हैं जिन गांव का टोटली आई.पी.एम. साहब को भी स्वयं पता है। पीने के पानी भी बहुत से गांवों में नहीं है। खारा पानी है। नहर का पानी भी बिल्कुल नहीं है। टेल पर सारी कांस्ट्रिचुएंसी है। अब यह हैड और टेल में बहुत अंतर है। आप भी स्पीकर साहब, इस बात के विचार करते हैं क्योंकि आपका हल्का भी टेल पर है। स्पीकर साहब वाटर अलाउंस सब जगह एक है। जैसे हिसार मेजर का 4.1, पेटवाड़ डिस्ट्रिक्ट्यूटरी का 2.5, सुन्दर ब्रांच का 2.4, न्यू माईनर का 1.9 और भाखड़ा का 2.4 है। अब आप देखें कि सुन्दर ब्रांच के हैड पर जो गांव हैं उनमें तो 70 और 80 परसेंट इरीगेशन है लेकिन जो टेल पर है, मेरा इलाका है, आपका इलाका लगता है, वहां केवल 7 परसेंट पानी लगता है। यह बात बड़ी अखरने वाली है जबकि वाटर रेट एक है और वाटर अलाउंस भी बराबर का लेते हैं। इसका हल तो सरकार को निकालना पड़ेगा। स्पीकर साहब, मुझे इस बात की खुशी है कि अब आई.पी.एम. साहब ने एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। इन्होंने अब यह किया है कि जिस ओवरसियर के एरिया में नहर कटेगी, उस

ओवरसियर के विरुद्ध केस बनेगा, उसको मुअत्तिल कर दिया जायेगा, उस पर मकदमा चलाया जायेगा। जबसे यह इस्ट्रक् ऑज जारी की गई है तब से हमारे इलाके में नहर नहीं कटी। तो किसानों के नाके सभी साफ होंगे जब यह हिदायते जारी कर दी जाये कि जिस सब डिविजन में, जिस एस.डी.ओ. के सरकल में मात्रा के मुताबिक पानी पूरा नहीं पहुंचेगा, वह एस.डी.ओ. सस्पेंड होगा। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से वे नाके साफ करते हैं। इस बात पर भी सख्ती कर देनी चाहिए।

जहां तक ट्रांसपोर्ट का सवाल है, स्पीकर साहब, यह बड़ा अच्छा काम कर रही है। जब से ने नेलाइजे इन ट्रांसपोर्ट का हुआ तब से इसने बहुत ज्यादा तरक्की की है। जब हरियाणा और पंजाब का पार्टी इन हुआ था उस वक्त हरियाणा के हिस्से में कुल 475 बसें आयी थी। आज हमारे पास 1850 बसें सन् 1975-76 के एंड तक हो जायेगी। यह बड़ा सराहनीय कदम है लेकिन अब तक जिस ढंग से इंतजाम होना चाहिए, अभी नहीं हो पाया है। हमारे यहां कृष्णा कम्पनी की बसें अब भी हिसार से दिल्ली चलती हैं। वहां पर हरियाणा रोडवेज की बसों में और उनमें कम्पीटी इन है। जहां ऐसा कम्पीटी इन हो, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमें वहां पर बड़ी अच्छी बसें रखनी चाहिये ताकि जो हमारा भोयर है, जो प्रॉफिट है वह प्राइवेट कम्पनी को न जाये, क्योंकि मैं देखता हूँ उनकी बसें हमारी बसों से पांच

मिनट पहले चल पड़ती है और वे वहीं खड़ी रहती है। इसलिये वहां पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाये।

स्पीकर साहब, मैं आपका एक मिनट और लूंगा। यह जो हमारे यहां कोआप्रेटिव मूवमेंट है, इसने भी प्रांत की उन्नति में बहुत हद तक हिस्सा लिया है। हमारे यहां 14 हजार कोआप्रेटिव सोसायटीज हैं जिनमें 253.47 करोड़ की इनवैस्टमेंट है लेकिन इस कोआप्रेटिव मूवमेंट से जो सहकारिता के आधार पर बनायी गयी थी वह पूरा फायदा नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। जो कोआप्रेटिव सोसायटीज का मैनेजमेंट बन जाता है उसको दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तो कुछ सख्ती हो गयी है लेकिन आज से चार साल पहले ऐसा था कि मैनेजमेंट बैंको से पैसा लेकर बोगस अंगूठे लगा कर, बोगस एन्ट्री करके पैसा अपने आप लेकर बैठ जाते थे। आज भी रिकवरी चल रही है। जहां भी सरकार के नोटिस में इस तरह के बोगस खाते आ जाये उन लोगों को बिल्कुल माफ न किया जाये उनको असलियत देख करके छोड़ा जाये। इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। जहां कोआप्रेटिव मूवमेंट है वहां पर कोआप्रेटिव बैंक आठ आठ और दस दस गांवों के लिये एक खोल दिया जाये। वहां से पास बुक बन जाये। जो एग्रीकल्चरिस्ट्स हो उनके लिये निर्धारित कर दिया जाये कि पांच किल्ले वाले को इतना लोन मिलेगा, 18 किल्ले वाले को इतना लोन मिलेगा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आयेगी। जो बिचौले जीपों में बैठ कर दौड़ते हैं, लोगों को तंग करते हैं वे

खत्म हो जायेंगे । सीधी ट्रांजैव इन बैंकों के साथ होनी चाहिए ।
स्पीकर साहब, एक और भी अजीब बात है कि इंडस्ट्री भाओअबे मे
तो दो परसेंट इंट्रैस्ट वसूल किया जाता है और एग्रीकल्चर भाओअबे
मे जिस पर सारादे 1 डिपेंड करता है नौ परसेंट और 14 परसेंट
और 14 परसेंट तक वसूल किया जाता है । इस फर्क को दूर
किया जाना चाहिए । ये जो रेट आफ इन्ट्रैस्ट मे डिस्क्रिमिने इन है
यह दूर होनी चाहिए । इन भाब्दों के साथ मैं फाईनैस मिनिस्टर
को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तस्वीर, खु अनुमा
तस्वीर सदन के सामने रखी है । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं
और स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे
बोलने के लिये समय दिया ।

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुईं)

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार): डिप्टी स्पीकर साहिबा,
कई दिनों से बजट पर चर्चा चल रही है । सब से पहले मैं अपने
वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने टैक्स फ्री
बजट सदन के सामने रखा है । सन् 1975-76 मे बजट मे 16.99
करोड़ रूपये का घाटा दिखाया गया है । इसमे से 6.63 करोड़
रूपया पहले साल का ब्रौट फारवर्ड है । वित्त मंत्री महोदय ने सदन
को वि वास दिलाया है कि इस घाटे को नये टैक्स न लागा कर
बल्कि बचत से या सैंटर की इमदाद लेकर पूरा करेंगे । जो उन्होंने
सदन को वि वास दिलया है कि उसके लिये भी मैं उनका बहुत
आभारी हूं ।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं ऐक्साइज एंड टैक्स इन डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। सैल्ज टैक्स ऐसा भाग है जिसका संबंध सीधा ट्रेडिंग क्लास है। ट्रेडिंग क्लास ने हमारे मुख्य मंत्री जी को यकीन दिलाया था कि अगर सरकार सख्ती से काम न ले और इन छापों को बन्द कर दिया जाये तो हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट को कोआप्रे इन देंगे और सैल्ज टैक्स में कमी भी नहीं आने देंगे। उन्होंने आंकड़ों से साबित कर दिया है, जो उन्होंने वि वास दिलाया था वह सही है और दुरुस्त रहा। वे अपने वायदे पर पूरे उतर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, सैल्ज टैक्स की जो इंकम हुई है वह इस साल में सन् 1974-75 में 32 करोड़ की हुई है। उसके बाद रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स 34 करोड़ के हैं और जो ऐस्टीमेटिड दिये हैं वे 37 करोड़ के हैं। इस बात के बावजूद पिछले साल बदतर किस्म का ड्राउट था और इंडस्ट्री घाटे में थी और वह इतनी ज्यादा थी कि अगर मैं यह कहूँ कि हाल्टिंग स्टेज पर आ गई थी तो कोई गलत बात नहीं होगी इस सब बातों के बावजूद आज हमारी सैल्ज टैक्स की वसूली निरन्तर इन्क्रीज हो रही है यह बात साबित करती है कि ट्रेडिंग क्लास गवर्नमेंट को पूरी कोआप्रे इन दे रही है। इसके साथ गवर्नमेंट ने ट्रेडिंग क्लास पर जो वि वास रखा है और जो सहूलियतें दी हैं उनके लिये मैं गवर्नमेंट का म कूर हूँ और ऐक्साइज एंड टैक्स इन मिनिस्टर साहिब का भी म कूर हूँ।

एक बात की तरफ मैं एक्सआईज एंड टैक्स इन मिनिस्टर साहब की अटैन्शन दिलाना चाहता हूँ। इंडस्ट्री पनप नहीं सकती जब तक सैल्जटैक्स के रेट्स जो हमारी बराबर की स्टेटस है जैसे देहली, यू.पी., पंजाब, हिमाचल और राजस्थान उनके बराबर न लाये जाये। कुछ चीजे ऐसी है जिनकी तरफ मैं अपने एक्सआईज एंड टैक्स इन मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूँ क्योंकि उनके सैल्ज टैक्स में बहुत डिसपैरिटी है जिस की वजह से इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा है। मुझे मंत्री जी ने वि वास दिलाया है कि नार्दन जोन की कांफ्रेंस में वे इस बात पर जोर डाल रहे है कि तमाम के तमाम रेट्स रीनेलाइज किये जाये, एक लैवल पर लाये। उन्होंने यह भी वि वास दिलाया है कि मार्च तक अगर वे कामयाब नहीं हुए तो मैटर को कन्सिडर करेंगे। तो मेरी गुजारि। यह है कि जो हमने कहा है उसकी तरफ ध्यान रखे और जल्दी से जल्दी कदम उठाये। अगर रीनेलाईजे इन आफ रेट्स हो जाये तो बहुत ही अच्छा होगा।

इसके बाद मैं इंडस्ट्री की चर्चा करना चाहूंगा। सदन में गवर्नर के अभिभाषण पर और एग्रीकल्चर पर जब चर्चा चल रही थी, कुछ बातें सामने आयी। मैं इस बात से सहमत हूँ जो दौलता साहब ने कही है कि जमींदारों की जमीन की तरफ ध्यान नहीं रखना चाहिए। उनका मतलब ठीक है। मैं उनकी इस बात से तो सहमत हूँ लेकिन मैं यह मानता हूँ कि आबादी जा रही है। आबादी की बढ़ती फ़ैमिली प्लानिंग सिस्टम से रूकने वाली नहीं है।

जमीन बढ़ नहीं रही है। आबादी घट नहीं सकती तो इस fragmentation of hildings कानून को छोड़िये, यह तो बढ़ती ही रहेगी। इसके अलावा उन्होंने यह कहा है कि सैंटर पर जोर देकर, यह जो लेडिज क्लास को, हमारी बहिन बेटियों को हक दिया है, उसमे तबदीली लाई जाये। उसके लिये मैं दौलता साहब से अर्ज करूंगा कि कोई ऐसी मो इन हाउस मे लायी जाये जिसके जरिए fragmentation of hildings बंद हो। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं पहले उन जमींदारो का जिक्र करना चाहता हूं जो परमानेंटली जमीन पर निर्भर रहने के लिये आंखे लगाये रहते है।

अध्यक्षा: जिस तरह से दौलता ने हाउस मे अपने व्यूज दिये है कि लड़कियों और बहिनो को हक नहीं मिलना चाहिये, इस बारे मे आप भी अपने व्यूज दीजिये।

श्री गुलाब सिंह जैन: मेरे व्यूज तो कलियर है। मैं तो दौलता साहब से हंडर्ड परसेंट सहमत हूं। वजह क्या है ? यह सब्जेक्ट इतना लम्बाहै, इस पर कभी रेजोल्यू इन आयेगा तो मैं डिटेल्ड बात करूंगा। हिन्दु ला मे जो हक नहीं होता था उसका बड़ा बहुत बड़ा कारण था। हमने वैस्ट से कापी करके इस चीज को किया है हालांकि मुझे मालूम है आपके सैव इन से चालीस पचास परसेंट वोट ले कर हम एम.एल.ए. बन कर आते है लेकिन हकीकत को ब्यान करने मे मुझे कोई तकलीफ नहीं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इंडस्ट्री के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। ऐग्रीकल्चर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उसको जो प्रायोरिटी दी है, वह ठीक है लेकिन जिस बुरे तरीके से इंडस्ट्री को इग्नोर किया गया है उस तरफ मैं सरकार का ध्यान मादबाना तरीके से दिलाना चाहता हूँ सारी प्लान के अन्दर जो 563 करोड़ रुपये का प्लान है, इंडस्ट्री का भोयर सिर्फ 14 करोड़ रुपये रखा गया है जो 2.5 परसेंट आता है। आज हमारे सामने अन एम्प्लायमेंट का भूत बुरी तरह से नाच रहा है। एन एम्प्लायमेंट को दूर करने का एक ही तरीका है और वह यह है कि हम इंडस्ट्री बढ़ सकती है इसलिये मैं सरकार से यह गुजारि । करूंगा कि इंडस्ट्री को बढ़ावा दे। हमारी जो पर कैपिटा इंकम है, जब तक ऐग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी वह तब तक नहीं बढ़ेगी और यहां पौस्पैरिटी नहीं आयेगी। हरियाणा इस मामले में खु । किस्मत है कि यह दिल्ली के सिरे पर बैठा हुआ है। दिल्ली एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ शहर है। अगर मैं गलती नहीं करता और मेरा ठीक साथ दे रही है तो सारे इंडिया के मुकाबले में दिल्ली सूबे की पर कैपिटा इंकम सबसे ज्यादा है और उस आमदनी को बहरहाल वे खर्च भी करते हैं। हरियाणा के अन्दर इस बात के बजाये कि हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की तरफ भागें, हमें छोटी छोटी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी प्रोडक्शन की हम दिल्ली में कंजम्पशन कर सकें। जब हम कंज्यूमर इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान स्माल स्केल इंडस्ट्री की तरफ आयेगा। बहरहाल स्माल स्केल

इंडस्ट्री के अंदर वह तबका ज्यादा काम करेगा जिसतबके कोहम मिडल क्लास या वीकर सैक इनकहते है। मैं अपनी सरकार से बड़ी मोअदबाना गुजारि । करूंगा कि वह स्माल स्केल इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दे। इंडस्ट्री के लिये बिजली पर कट लगे। आी कल ही हमे यहां पर यह खु ।खबरी दी गयी कि फरीदाबाद के 60 मैगावाट के प्लांट ने प्रोडक् ।न भुरु कर दी है उसमे से 40 मैगावाट बिजली हमें मिलेगी। एग्रीकल्चर के लिये बिजली देना बिल्कुल सही है लेकिन मैं गुप्ता साहब से यह अर्ज करूंगा कि ऐग्रीकल्चर का ध्यान दखते हुए उस छोटे अभागे इंडस्ट्रीयलिस्ट का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जिसने पु ।तों से अपने खून पसीने की कमाई ही नहीं बल्कि लोगों से कर्जा लेकर और बैंकों से कर्जा लेकर पैसा लगाया है। आज मनी मार्किट बड़ी टाईट है। 17-18-19 परसेंट, रेट आफ इंट्रेस्ट हो गया है। उसकी वर्किंग कैपिटल नश्ट हो जा रही है। इसलिये जैसे कि आपने कहा है कि 40 मैगावाट बिजली हमको मिलने लग जायेगी उसका कुछ हिस्सा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को जरूर मिलना चाहिए ताकि कम से कम वे अपने कल कारखाने इस लैवल पर तो चला सके कि मजदूर को मजदूरी दे सके, अपने दफतर के बाबुओं को तनख्वाह दे सके और रकम का ब्याज दे सके। कम से कम उन्हे इतनी रिटर्न तो मिल जाये, इतनी चीज हमे जरूर कर देनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने यहां फरमाया है कि जमींदार को हम 6 घंटे बिजली देना चाहते है, तो उस छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को कम से कम इतनी बिजली जरूरदे जिससे कि वह अपनी इंडस्ट्री को रनिंग कंडी ।न मे रख सके औरबिल्कुल

ही दिवालिया न हो जाये। यह मेरी बड़ी मोअदवाना अर्ज है। इसके साथ ही इंडस्ट्री के बारे में एक और अर्ज करना चाहता हूँ कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उनको प्राइवेट सैक्टर में प्रोत्साहन न दिया जाये। उनकी जो ऐम्पलायमेंट पालिसी होती है, वह एंटी हरियाणा होती है। मुझे इस बात का पर्सनल तजुर्बा है। मुझे एक मिल के बारे में मालूम है। वह मिल एक बहुत बड़ा युनिट है। उन्होंने एज ए मैटर आफ पालिसी यह बना रखा है कि जो लेबर के लिये रिक्रूटमेंट करनी है वह हरियाणा के बाहर से करनी है मेरी उसे एक दफा इस बारे में बात हुई। मैंने उनसे सवाल किया कि आप हरियाणा की लेबर क्यों नहीं रखते तो उन्होंने यह कहा कि अगर हम लोकल लेबर रख लेते हैं तो जब स्ट्राईक करते हैं तो बड़े आराम से अपने घर चले जाते हैं। अगर हम बाहर की लेबर रखते हैं तो वे इतनी दूर जा नहीं सकते, भूखे मरते हैं इसलिये स्ट्राईक करने की जुर्रत नहीं करते। मतलब यह कि बाहर की लेबर कैपिटेलिस्ट के अंगूठे के नीचे रहती है। जब भी कैपिटेलिस्ट उनको दबाना चाहे, दबा सकता है। वे मजबूरन कैपिटेलिस्ट के अंगूठे के नीचे दबे रहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी यह पालिसी रहती है कि वे लेबर हरियाणा से बाहर की लाये। तो उने पास लेबर हरियाणा से बाहर की होती है और उनके हैड आफिस भी हरियाणा से बाहर होते हैं। हमको उनसे इंकम का भोयर भी नहीं मिलता और नहीं ही सेल्ज टैक्स मिलता है। क्योंकि उन्होंने अपने हैड आफिस और सेल्ज आफिस बाहर रखे हुए हैं। अगर

स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किये जाये तो पता चलेगा कि जमीन जो उन्हें सस्ती दी जाती है, वह हमारे जमींदार की है, सारे फाईनैस हरियाणा सरकार के है, बिजली जिसकी हमको बहुत सख्त जरूरत है, वह हरियाणा सरकार से मिलती है लेकिन मुलाजमत के लिये वह अपने किसी रि तेदार, भाई भतीजों को और दूसरी जगहों से ले आते है। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। इसलिये मेरी अर्ज यह है कि जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं गुप्ता जी से यह कहना चाहूंगा कि जिस वक्त आप बिजली देने की बात सोचे तो आप उन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन न दे। ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन हो। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एक ऐसा यूनिट है जिसमे कैपिटेलिस्ट स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की कास्ट पर पलता है। इसलिये इस चीज की तरफ महकमा बिजली को भी और महकमा इंडस्ट्रीज को भी ध्यान देने की जरूरत है।(व्यवधान).... मुझे खु शी है अगर आप ऐसा सोच रहे है। मेरा मुछ्दा तो यही था कि आप मेरी बात समझे और माने। हरिजनों की बाबत मेरे भाई अमर सिंह ने बहुत अच्छा कहा कि हरिजनो को जमींदारों की जमीन नही चाहिए। उन्हें तो रोजगार चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं। रिजर्वे ान तो एक लानत है। यह तो हमने एक खास पीरियड के लिये रखी थी ताकि हम हरिजनों को बराबरी के लैवल तक ला सके। लेकिन देखना यह है कि क्या हम उनको अपने बराबर लाने मे कामयाब हुए है? मैं इस बात मे ऐग्री करता हूं कि 25 साल से भी ज्यादा की आजादी के बावजूद भी, हमारी सारी ऐफर्टस के

बावजूद भी, उन लोगों को जो हमारे सालों तक बेकवर्ड रहे और इग्नोर्ड रहे, हम बराबर नहीं ला पाये हैं। उनको बराबर लाने का एक ही तरीका है कि हम इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। मेरी आपके द्वारा आपनी सरकार से बड़ी मोअदबाना गुजारि है कि after agriculture they must give the greatest priority, importance and emphasis on industry.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, वह तालीम के बारे में कहना चाहूंगा। जहां पर तालीम की काफी चर्चा चली और अन एम्प्लायमेंट की भी बात चली। मैं यह चाहूंगा कि सरकार स्टेट में क्वालिटी आफ ऐजुकेशन इम्पूव करे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने अन एम्प्लायमेंट की कुछ फिगर्ज इकट्ठी की है जिन्हे मैं सदन में रूबरू करना चाहता हूँ। यह एक बड़ी रिवीलिंग चीज है। मैंने कल यह आंकड़े पढ़े हैं। मेरे पास पिछले सालों यान 1969 से अब तक के आंकड़े हैं। मैं पिछले सालों की बात नहीं करता मैं। 1973-74 की बात करता हूँ। जो लाईव रजिस्टर पर एम्प्लायमेंट के लिये रजिस्टर्ड है उनका नम्बर है 70551। इसमें से जो मैट्रीकुलेट या इंटरमीजियेट रजिस्टर्ड है उनकी तादाद 55585 है। मेरा कहने का मतलब यह है कि लाइव रजिस्टर पर 79 प्रतिशत वह लोग हैं जो या तो मैट्रीकुलेट हैं या इंटरमीजियेट हैं। अगर 1969 से अब तक आंकड़े देखे तो पता चलता है कि किसी साल में यह परसेंटेज 82 है, किसी में 82.9 है तो किसी में 79 है। प्रैक्टिकली हर साल जो लोग रजिस्टर्ड हैं उस में से 80 से लेकर 86 परसेंट तक ऐसे लोग हैं जिनकी

स्वालीफिके इन या तो मेट्रीकुले इन है या इंटरमीजिएट है। इस का मतलब यह है कि हमारे यहां जो दूसरे लोग हैं उनका नम्बर इतना ज्यादा नहीं है जितना कि मैट्रिक या इंटरमीजिएट का है। वह तादाद कोई ज्यादा नहीं है। अगर हम ऐजुके इन के स्टैंडर्ड को इम्पूव कर दे तो बहुत ज्यादा आदमी तो हमारे जो बराबर का दिल्ली सूबा है, उसमें खप सकते हैं। वहां पर जितने ही स्टैनोग्राफर्ज और अकाउंटैंटस की जरूरत है लेकिन उन्हें मिलते ही नहीं है। अगर प्रौपर्टी लोग क्वालीफाईड हो तो वहां पर उन्हें पांच सात आठ सौ रूपये की नौकरी बड़े आराम से मिल सकती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमें चाहिए कि हम हाई स्कूल खोलना छोड़ दे। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि चौधरी माडू सिंह जी जो हर वक्त यहां बैठे रहा करते हैं, इस वक्त बदकिस्मती से यहां मौजूद नहीं है। मैं सरकार से बड़ी मोअदबाना अर्ज करूंगा कि जल्दी से जल्दी एक हाई पावर्ड कमेटी ऐजुके इन सिस्टम को रिवाइज करने के लिये हरियाणा में बनायी जाये। आज वह लड़का जो एक देहात के स्कूल से निकलता है और वह लड़का जिसके मां बाप हम यह कह सकते कि परमात्मा उन पर राजी है, सिलवर स्पून लेकर पैदा हुआ है और पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, जब वह मार्किट में आता है तो देहात वाला लड़का उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं पब्लिक एंस्टीच्यू इंज के खिलाफ नहीं हूँ। पब्लिक स्कूल का मतलब है क्वालिटी स्कूल। आज ही टाइम्ज आफ इंडिया में एक आर्टिकल है सच फार आइडैन्टिटी। हमको ऐजुके इन की स्वालिटी में

इम्पूवमेंट करना पड़ेगा। आठवीं जमात तक जनरल ऐजुकेशन रखनी चाहिए क्योंकि आठवीं तक इंगलिश रखने की जरूरत नहीं है। हिन्दी हमारी मातृभाषा है, हिन्दी हमारे दफ्तरों में चलती है, हिन्दी में काम हो सकता है। इसलिये ऐलजैबरा और ज्योमैटरी की क्या जरूरत ? जब हमको किसी टेक्नीकल ऐजुकेशन में जाना हो तब इन चीजों की जरूरत पड़ती है। हमने ऐलजैबरा और ज्योमैटरी पढ़ी थी हमारे किस काम आई। आज रोजमर्रा की जिन्दगी में जिस ऐजुकेशन की जरूरत पड़ती है वह आठवीं जमात तक पूरी हो जाती है। आज हम देखें कि हम अपने बजट में ऐजुकेशन पर कितना खर्च करते हैं। मेरा अंदाजा है। कि ऐजुकेशन पर जो हम खर्च कर रहे हैं वह 32 करोड़ है। लेकिन अगर इसमें से एक रकम निर्धारित इस बात के लिये कर दे जिससे वीकर सैव इन का फायदा हो तो अच्छी बात होगी। मैं तो रैजिडेंट्स अल स्कूल के हक में हूँ। रैजिडेंट्स अल स्कूल खोलकर हम इम्पूवमेंट इन ऐजुकेशन कर सकते हैं। अगर हम क्वालिटी स्कूल खोलते में कामयाब नहीं होते तो रैजिडेंट्स अल स्कूल खोल दें और तभी यह ऐजुकेशन की प्रॉब्लम हल हो सकती है। ऐजुकेशन पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह इस तरफ ध्यान दे।

डिप्टी स्पीकर सहिबा, सिविल सप्लाइ के बारे में चंद भाब्द कहना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि जब से यह महकमा हमारे मौजूदा सिविल सप्लाइ मिनिस्टर के पास आया है, काफी

स्मगलिंग के केस पकड़े गये है और वह अच्छी बात है। प्रोक्योरमेंट भी अच्छी हुई है। एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि ऐग्रीकल्चर मे पैडी की प्राइसिज पंजाब के मुकाबले ज्यादा मिली है और इससे हम काफी फायदा हुआ है। लेकिन एक चीज मैं उनसे इस बारे मे अव य कहना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यू इन मे कोई ऐसा सिस्टम हरियाणा मे कहना चाहिए कि यह जो डिपोज पर क्यू लगती है उनको दूर किया जाये। इसके ऊपर हमें बैठकर सोचने की जरूरत है। बाकी सब ठीक हैं इससे ज्यादा मैं। इस बात के बारे मे कुछ नही कहना चाहता।

एक प्रौब्लम मेरे हल्के की और है। मुख्य मंत्री जी यहां नही बैठे है। वह प्रौब्लम पोलिटीकल सफरर्ज की है। मेरे हल्के मे उन लोगों को जमीने मिली थी कि उन्होंने अपनी जवानियां अंग्रेजों की जेलों मे काटी। उनकी कुछ समस्याए थी, कुछ गलतफहमियां थी, जिसके लिये अलाटमेंट पर झगड़े चले। कुछ लोग हाई कोई मे गए और वह वहां से जीत गए। लैटर पेटेंट अपील उन पालिटीकल सफरर्ज के हक मे हो गया। मैं मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उनके केसिज को सिम्पेथैटिकली ट्रीअ किया जाये। वे मुझसे हिसार मे मिले थे ओर कहते है कि वे सरकार के साथ है। उन्होंने इस देा के लिये आजादी दिलाने मे बहुत काम किया है। उनमे से बहुतों को तो फांसी होने बची है। उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी रही हैं उनकी कुर्बानी की वजह से ही

हम यहां बैठे हैं। मेरी प्रार्थना है कि उनके केसिज को हमदर्दना तरीके से ट्रीट किया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, ट्रांसपोर्ट के बारे में चंद बातें कहना चाहता हूँ। जैसे तो ट्रांसपोर्ट पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी ट्रांसपोर्ट हिन्दुस्तान के अंदर बेहतरीन समझी जाती है लेकिन फिर भी काफी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। कल ही मैं। इसके प्रोफिट और लौस के आंकड़े देख रहा था, बैलेन्स भीट स्टडी कर रहा था। मैं एक बात देखकर हैरान था कि आज हमने 25 से 50 फीसदी तक ओवरलोडिंग की इजाजत दी है। लेकिन इसके बावजूद जो रिटर्न है वह इन्वैस्टमेंट के कोमेंसुरेट नहीं है। इस बारे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को खास ध्यान देना चाहिए। जो सेल्ज आफ टिकट से रिटर्न है और जो मुनाफा है, 25 प्रति सत ओवरलोडिंग भी है लेकिन फिर भी 55 लाख का मुनाफा दिखाया गया वह नाकाफी है। मैं उस मुनाफ को ठीक नहीं समझता। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि कहीं न कहीं लकूना है उसको कैसे ठीक किया जाये और जो मेरे से सुझाव दिया जा सकता है वह सुझाव मैं दूंगा। लेकिन मैं उनका ध्यान सफाई की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बसों में सफाई है लेकिन मैं इस मामले में उनके साथ डिफर करता हूँ। अपनी बसों की हालत को देखने के लिये हमारी ट्रांसपोर्ट कैसे रन कर ही है, मैं हर महीने दो दफा बस में ट्रैवल करता हूँ और मैं अपनी आइडेंटिटी डिसक्लोज नहीं करता क्योंकि मैं अगर कह दूँ कि मैं

एम.एल.ए. हूं, मैं टिकट नहीं लेता तो फिर ठीक नहीं रहता। इसलिये मैं टिकट खरीदता हूं। मेरा कहना यह है कि आप कंडक्टर को यह ट्रेनिंग दे कि वह बिजनैस के तरीके से बसों को चलाये। उनका फर्ज बनता है कि जो सवारियां हैं वह उनको कस्टमर समझे और उस कस्टमर की सर्विस करे, हकूमत न करे। उनका जो हुक्मराना रवैया है वह नहीं होना चाहिए। अभी परसो ही जो उनकी यूनियन के सैक्रेटरी हैं उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि चौधरी साहब आप अपने लोगों को समझाओं। उन्होंने कहा कि कुछ कंडक्टर जो हैं वे गलत किस्म के हैं अगर कोई ऐकान लिया जाता है तो फिर उनकी सिफारिश आती है। मैंने उनसे कहा कि जो सब से ज्यादा सिफारिशें हैं वे एम.एल.ए. साहिबान की आती हैं। मुझे याद कि कि पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें मुख्य मंत्री भी थे और उन्होंने कहा कि कोई भी एम.एल.ए. किसी गलत कंडक्टर की सिफारिश न करे। जिनके खिलाफ कोई शिकायत है वह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नोटिस में लाओ। किसी को भी सिफारिश न करनी चाहिए। मैं एम.एल.ए. साहिबान से अर्ज करूंगा कि वे इसबात का खास ख्याल रखें कि वे किसी सिफारिश न करे। एक और चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे रेलवेज के अंदर होता है कि जब मेन स्टेप आता है और 10-15 मिनट गाड़ी रुकती है तो वहां कम्पार्टमेंट की सफाई होती है। इसी तरह से हमारी बसों में भी होना चाहिए। जो मेन स्टेप है जहां डिपोज बने हुए हैं वहां जब बस पहुंचे तो वहां सफाई करने वाला आना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हिसार

से बस चली दिल्ली के लिये और दिल्ली से गन्दी बस ही वापिस हिसार कि लिये चल दी। इससे जो दूसरी स्टेट के लोग होते है उन पर गलत इम्प्रेसन पड़ता है। मामूली से खर्च से, मामूली से ध्यान देने से सफाई हो सकती है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यूरिनल्ज की बाबत है। मैंने देखा है कि स्टेज पर लोग दीवार के साथ खड़े हो जाते है और वह बुरा लगता है। परसों भी मैंने हिसार के बस अड्डे के बारे मे कहा था। ठीक है उसे माड्रेनाइज न किया जाये क्योंकि हमारे पास धन की कमी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां कमि नरीका हैडक्वार्टर है, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां का बस अड्डा ठीक तो हो। वहां पर पचास हजार रूपया खर्च कर दिया जाये। कुछ युरिनल्ज ही बना दिये जायें तो उसकी दीवारे अच्छी हो सकती है लेकिन सिर्फ इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, ट्रांसपोर्ट के बारे मे मैं अपने हल्के की दो तीन बातें जरूर कहना चाहता हूं। हिसार एक बढ़ता हुआ भाहर है। वहां मिनी सैक्रेटेरियट बना है और कचहरी जो है वह नये कम्पलैक्स मे चली गई है। उधर दूसरी तरफ हिसार का इलाका ज्यादा दिल्ली रोड पर बढ़ा है। इसलिये वहां पर जो लोकल बस सर्विस है वह काफी नही है। स्कूटर और रिक्सा वाले लोग दो दो रूपये पास पास जाने के लिये मांग लैते है जो कि एक गरीब आदमी देने मे असमर्थ होता है। इसलिये मेरी गुजारि है कि एक तो कचहरी के टाईम पर सुबह और दूसरा कम से कम

भाम के टाइम के लिये एक दो बसें चला दी जाये ताकि जो ऐम्पलाईज वगैरा या दूसरे लोग दूर दूर से आते है उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। हम यहां चण्डीगढ़ मे भी देखते है कि सैक्रेटेरियेट के लिये सुबह भाम दोनों टाइम बसे आती जाती है जिससे लोगों को बड़ी सहूलियत है। अतः इसी प्रकार वहां भी बसों की प्रोवीजन होनी चाहिए। एक एक घण्टे की बस सर्विस की बजाये 15-15 मिनट के बाद बसें आनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि हिसार भाहर अब दो हिस्सों मे बटता जा रहा है एक रेलवे पुल को राइट पर और दूसरा उसकी लेफ्ट पर। माडल टाउन के साथ इंडस्ट्रियल ऐस्टेट भी है। वहां पर भी लेकिन बस सर्विस नाकाफी है। इसलिये मेरी मुजारि है कि यदि वहां पर लोकल बस सर्विस 10 और 15-15 मिनट के बाद करदी जाये तो म। सरकार का बड़ा ही म कूर हूंगा। इससे लोगों को बड़ा आराम हो जायेगा और जो गरीब आदमी बहुत रहते है। मीडियम फैमलीज है जोकि स्कूटर वगैरा को अफोर्ड नही कर सकते है। कुछेक फैमिलीज को आप छोड़ दो। उनको छोड़कर या तो इन इलाकों मे ऐम्पलाइज रहते है या फिर दुकानदार रहते है। साथ ही माडल टाउन मे बच्चों के लिये एक स्कूल है। दो दो चार चार मील की दूरी पर जो लोग रहते है उनके बच्चों को आने जाने मे बड़ी तकलीफ होती है। स्कूटर रिक् गा वाले 2-2 चार चार रूपये से कम से कम पैसे नही मांगते। मेरे अपने हल्के मे एक गांव बीड़ है जिसकी आबादी कम से कम 10 हजार के करीब है और वहां पर एक स्कूल है जोकि 4 मील की दूरी पर है। हमारे

उस एरिये के बच्चों लड़के लड़कियों को वहां पर जाना पड़ता है। लोकल बस सर्विस अवेलेबल न होने के कारण बड़ी दिक्कत है। तो मेरी आप के द्वारा सरकार से गुजारि है कि लोगों की इन तकलीफों को देखते हुए वहां पर लोकल बस सर्विस भुरु की जाये और एक बस कम से कम बचों के स्कूल टाईम के लिये सुबह और भाम चालू की जाये ताकि बच्चों को भी इतनी दूर जाने आने मे मुक्ति कल पे न आये।

डिप्टी स्पीकर सहिबा, इसके बाद मैं पब्लिक हैल्थरा की तरफ आता हूं। मैं अपने हल्के के बारे मे, (जो मेरा रिवाइज्ड हल्का है) कहना चाहता हूं। उस मे केवल 3 विलेज रह गये उनमे दो गांव ऐसा है, जिनको पानी देने की समस्या है। एक गांव ऐसे है, जिनको पानी देने की समस्या है। एक गांव ऐसे है, जिनका पानी कमि नर साहब की कोठी को जाना है, वोस्टल जेल को जाना है, गवर्नमेंट कालेज को जाना है, सैक्रेटिगट को जान है, और वहां पर जो गवर्नमेंट ऐम्पलाइज के क्वार्टर्ज बने है, उनको जाना है। तो मेरी सिर्फ यह रिक्वेस्ट है कि उस वाटर वर्क्स से पाइपस वगैरह की ऐक्सटेंशन उस गांव की तरफ भी कर दी जाये तो उस गांव को भी पाने का पानी मिल जायेगा और ऐसा करने से कोई खास खर्चा भी नहीं होगा। एक और गांव है तलवन्डी नाना। बदकिस्मती से वहां पर कंसौलीडेड न आफ होल्डिंगज नहीं हो सकी क्योंकि इस मामले को कई लोग सुप्रीम कोर्ट तक ले गये। वहां पर पंचायतों के पास जमीन नहीं है। वे बैनीफिटियरी

भोयर भी नहीं दे सकते। इसलिये मेरी सरकार से गुजारि है कि सरकार वहां पर वाटर वर्कस लगाने के लिये उन से बैनीफि टायरी भोयर न ले और अपने ही खर्चे पर सब कुछ करे। इससे आगे मैं एक बात और बताता हूं। एक जुगलांग गांव है। वहां की पंचायत के ब्लाक से मुझे पता गला है कि एक गांव के कुएं में एक औरत ने छलांग लगा कर खुदक मी कर ली और उसका पानी इतना गन्दा है कि लोग उसको पी नहीं सकते। वह पानी बहुत गहरा भी है। लोगों ने वहां पर उसको साफ करने के बड़े प्रयत्न भी किये हैं। लोगो ने चरसों के जरिये भी सब कुछ किया है लेकिन उस कुएं का कुछ नहीं कर सके। पब्लिक हैल्थ वाले भी हमको आज तक टरकाते ही रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने पब्लिक हैल्थ के ऐग्जैक्टिव इंजीरियर से भी खुद मिलकर बात की लेकिन फिर भी वहां पर सफाई वगैरह का कोई प्रबंध नहीं हुआ। उस गांव की पंचायत का यह जवाब था कि हम खुद अपने पल्ले से पांच सौ सात सौ रूपया भी लगाने के लिये तैयार हैं, लेकिन यह काम सरकार करवा दे, क्योंकि लोगों के पास इस काम को करने के लिये मं टायरी नहीं है। मं टायरी के बिना आप ही बताइये कि वे बेचारे क्या कर सकते हैं ? तो मेरी इस सरकार से पुरजोर अपील है कि है कि ज्यादा से ज्यादा इस काम को एक हफ्ते के अंदर अंदर करवा दिया जाये। मैं इस बारे में किसी अफसर की टिकायत नहीं कर रहा हूं, हमारी तो सिर्फ यही प्रार्थना है कि यह काम जल्दी से जल्दी करवा दिया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इससे आगे मैं सड़कों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। गवर्नमेंट की आप पालिसी है कि कोई नई सड़क न बनाई जाये। इस पालिसी से मुझे एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे अपने हल्के के इंट्रैस्ट को तो देखना होगा। एक गांव भाहपुर नू है। वह गांव तलवन्डी रान से डेढ़ दो मील के फासले पर है। एक गांव में स्कूल है और दूसरे में स्कूल को अप ग्रेड इसलिये नहीं किया गया कि पास पास स्कूल है, पर वहां पर सड़क भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के वे भाब्द याद है— “We have entered into cycle age.” आजकल स्कूलों में जाने के लिये आमतौर पर लड़के लड़कियों साईकिलों पर जाते हैं, पर आप ही बताइये कि अगर सड़कें ही न होंगी, तो फिर लोग साईकिल पर जा नहीं सकेंगे। इस लिये कि अगर सड़कें ही न होंगी, तो फिर लोग साईकिल पर जा नहीं सकेंगे। इस लिये मेरी सरकार से गुजारि है कि इस बजट में जो मॅटीनॅस के लिये रकम रखी गई है, उसमें से कुछ रूपया निकाल कर अगर यह सड़क का काम करवा दिया जाये, जिसके ऊपर कोई खास रूपया भी नहीं लगेगा, तो मैं उनका बहुत ही भुक्रगुजार होऊंगा। मुख्य मंत्री साहब, अभी यहां पर नहीं है। उन्होंने इसबारे में एक बाद वहां जाकर स्पीच भी की थी। मेरे पास टेप नहीं था। अगर उनकी स्पीकच टेप की होती, तो मैं सुना भी देता। उन्होंने कहा था कि हम यह सड़क बनवा देंगे, लेकिन आज तक यह काम नहीं हुआ।

इसके बाद मैं कौनाल्ज के बारे में भी कहूंगा। यहां पर चर्चा चल रही है। कि इसके लिये ऐनुअल प्लैन में 60 परसेंट अमाउंट रखा है। मैं इसका स्पोर्टर हूं। हिसार के अन्दर कुछ एरिया ऐसा है जहां पर लिफ्ट इरीगेशन की जरूरत है। जुगलाण गांव की भी छोटी सी स्कीम मेरी प्रार्थना है कि इस लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत उस इलाके को भी पानी मिलना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह सब बातें भी, जो कि मैं आपके जरिये सरकार के नोटिस में लाना चाहता था। आशा है कि सरकार जरूर मेरी इन बातों पर ध्यान देगी। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री गौरी भांकर (नरवाला): डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे फाईनैस मिनिस्टर साहब ने यह जो बजट हमारे सामने रखा है मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा बजट है। इसमें सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। इसके लिये मैं अपनी सरकार को व फाईनैस मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ मैं यहां पर कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। आज जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और हमारे यहां पर बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है इसके लिये मेरा एक सुझाव है कि हमें जल्दी ही स्माल स्केल इंडस्ट्री को लगाने के लिये कोई पग नहीं उठाएंगे तब तक यह बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकेगी। हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, वह एग्रीकल्चर में बहुत कम रुचि लेते हैं, अक्सर तो वह यह एग्रीकल्चर का काम ही नहीं करना चाहते। (इस

समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी मनफूल सिंह पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे बच्चों का जो ट्रेंड है, सरकार को उनके मुताबिक ही चलना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऐग्रीकल्चर में कोई इतनी खास दिलचस्पी नहीं लेते। जब तक उनका ट्रेंड इंडस्ट्रीज की तरफ न लाया जायेगा, उस वक्त तक हमारे यहां की यह बेरोजगारी दूर नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार को तजवीज पे करता हूं कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के बढ़ावे के लिये हमें एक बोर्ड बनाना चाहिये, जो इस चीज को देखे कि हमारे हरियाणा में स्माल स्केल इंडस्ट्री कहां कहा चल सकती है। खास करके रूरल ऐरियाज में इस चीज को देखा जाना चाहिए। अगर हम स्माल स्केल इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लगायेंगे तो इसकी प्राडक्ट्स को हम बाहर भेज कर भी फायदा उठा सकते हैं। इस इंडस्ट्री को लगाने के लिये यह भी जरूरी है कि हम दूसरे मुल्कों में जाकर देखें कि वहां की इंडस्ट्री किस तरीक से चलती हैं जैसे जापान है, वहां पर इतनी इंडस्ट्री है कि वहां के लोगो को जरूरत से ज्यादा रोजगार मिलता है। तो हमें वहां जाकर भी इसचीज की इनक्वायरी करनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके लिये एक बोर्ड या कमेटी बने वह बाहर के मुल्कों में स्टडी करके आए और फिर जैसा सुझाव वह बोर्ड या कमेटी दे, उसके मुताबिक सारे भारतवर्ष में हमें स्माल स्केल इंडस्ट्री लगानी चाहिए। आज कल जो हमारे बच्चे हैं, वे नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। एक एक एम.एल. के पीछे आजकल दो दो तीन तीन सौ बच्चे लगे रहते हैं कि हमारी

नौकरी लगवाओं । तो इतने बच्चों को राजगार दिलवाना एक एम. एल.ए. के बस की बात नहीं है । इसलिये चेयरमैन साहब मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आजकल के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको किसी इंस्टीरूचूट में ट्रेनिंग दिलवा कर उनकी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगवाई जाये । इस समय अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश भी करता है, तो उसको बड़ी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि लोन देने के हमारे जो कायदे कानून हैं, वे बहुत ही ज्यादा भारते रखते हैं, जिनको कि हर आदमी पूरा नहीं कर सकता । इसलिये वे भारते भी आसान बनाई जानी चाहिए, ताकि वे लोग लोन वगैरह लेकर अपना काम चला सकें । इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार की सेवा में अर्ज करना चाहता हूँ कि इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाये । अगली बात में खेतीबाड़ी के मुताल्लिक कहना चाहता हूँ । आज खेतीबाड़ी में भी काफी सुधार की जरूरत है और हरियाणा सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । इसके अलावा हम जो खाद और बीज किसानों को देते हैं, वह देने से पहले इस चीज को देखा जाना चाहिए, कि कौन सा बीज कौन सी जमीन के लिये ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे जमींदारों को पता नहीं होता कि कैसी जमीन पर कैसा बीज डालना चाहिए । इसके लिये एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाई जाये, जो कि इस चीज को देखे कि कौन से इलाके के लिये कौन सा बीज और कौन सी खाद उपयुक्त है । इस समय हमारी ऐग्रीकल्चर का जो काम है, वह बिल्कुल ठप्प है । पहले हमारे यहां ग्राम सेवक होते थे, जो कि खेतीबाड़ी के मुताल्लिक थोड़ी बहुत सहायता देते

थे, लेकिन अब ग्राम सेवक जो है उनकी पोस्टें खत्म करके पंचायत सैक्रेटरी बना दिये गये हैं। पंचायत सैक्रेटरी जो है, वे इस काम को नहीं करते हैं, इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ग्राम सचिव की पोस्टें फिर बनाई जाये, बल्कि पहले से भी ज्यादा बनाई जाये और जो पंचायत सैक्रेटरी जो है, उनसे यह काम न लिया जाये, वे पंचायत का काम सम्भालें। इन लोगों को एरिया बांट देना चाहिए और उस एरिया में ये लोग जाकर किसानों को बताएं कि आपको इस इस किस्म की खाद और बीज इसतेमाल करने चाहिए कि जिस वक्त बीज का सीजन आए, उससे कम से कम दो महीने पहले बीज आ जाना चाहिए। अब क्या होता है कि बीज लेट आते हैं, और किसान उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते इसलिये वह मार्किट में चले जाते हैं और वहां उनका नाजायज फायदा उठाया जाता है। इसलिये सरकार से मेरी फिर प्रार्थना है कि बीज और खाद का सीजन के मुताबिक इंतजाम होना चाहिए। एक चीज और कि जो बीज आते हैं, वे अच्छी किस्म के नहीं आते। पिछली दफा मैंने बताया था कि बाजरे का हमारा कितना नुकसान हुआ। तो उसवक्त कहा गया कि यह नैनल सीड कार्पोरेट्स से आया है। अगर बीज ठीक न आने की वजह से जमींदार का नुकसान होता है तो उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिये और जिस एजेंसी ने ऐसा बीज सप्लाई किया है उसके खिलाफ एक नैनल होना चाहिए। लेकिन ऐसी एजेंसियों के खिलाफ चूंकि एक नैनल नहीं लिया जाता है इसलिये वे खराब बीज ही बनाती रहती हैं। सरकार से मेरी फिर प्रार्थना है कि खेती बाड़ी के

लिये जो बीज आये, वह अच्छी किस्म का आए ताकि हमारी पैदावार में बढौतरी हो सके। अगली बात यह कि हमारे जो नौजवान लड़के हे, उनके लिये सरकारको चाहिए कि वह एक सैंअर कायम करे ताकि वे ऐग्रीकल्चर के बारे में वहां से पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सके। इस समय जो तालीम का सिस्टम हे, यह सिस्टम ठीक नहीं है ? सरकार को चाहिए कि आठवीं के बाद लड़कों को ऐसी शिक्षा भुरु करवा देनी चाहिए। आठवीं के बाद जो लड़का इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहे उधर जाए और अगर ऐग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहे, तो उधर चला जाये। अगली बात मैं बिजल के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। बिजली की आत कल हमारे हरियाणा में बहुत भार्टेज है। यह ठीक है कि बिजली के लिये हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है और मैं इसके लिये सरकार की सराहना भी करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने एक बात बहुत गलत भी की हुई है। वह यह है कि जब हम किसी को बिजली स्पेयर थी, उस वक्त हमने यह एम.सी.जी. क्यों लगाए ? जिसवक्त हमारे पास बिजली स्पेयर थी, उस वक्त हमने यह एम.सी.जी. वसूल करने का हमें कोई हक नहीं है। इसलिये चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से अर्ज करुंगा कि इसको हटाया जाये। आपको तो लोगो का भुक्रिया अदा करना चाहिए कि वे बिजली कम इस्तेमाल करते है। दूसरे बिजली का जो नीचे का स्टाफ है, जैसे एस.डी.ओ. या लाइन सुप्रिन्टैंडेंट वे लोगो को बहुत हैरान करते है। अगर किसी अदमी को कनैक्शन लना होता है तो वे कहते है कि हमारे पास सामान नहीं है। ठीक है सामान की

भार्तेज है, लेकिन बोर्ड जो उनको थोड़ा बहुत सामान देता है उसका वह नाजायज फायदा उठाते हैं। जो आदमी तो उनको दो चार सौ रूपया दे देता है, उसको तो सामान भी मिल जाता है और कनैक्शन भी मिल जाता है और जो गरीब आदमी पैसा नहीं दे सकता, उसको जवाब दे देते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आज कल जबकि इंडस्ट्री को भी बिजली कम मिलती है, तो उसके ऊपर भी एम.सी.जी. बंद करनी चाहिए। अगली बात यह है कि देश में जो आबादी बढ़ रही है, उसको रोकने के लिये हमारे फैमिली प्लैनिंग का काम भी ठीक नहीं है। आज कल जो सिस्टम बनाया हुआ है उसमें तमाम अफसरों को ड्यूटी लगाई हुई कि तुम इतने केस दो और तुम इतने दो। ऐसा करने से जो एस.डी.एम. तहसीलदार या और दूसरे अफसर हैं, उनके अपने काम में बाधा पड़ती है। इसलिये मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को हमें निवेदन करना चाहिए कि वह ऐसा कानून बनाए ताकि कानूनी तौर पर सबको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। अगर यह न हो सके, तो सरकार कोई और इंतजाम करें ताकि दूसरे अफसरों को अपने काम में नुकसान न उठाना पड़े।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी जो मार्किट कमेटियां हैं, उनकी आमदनी का 60 फीसदी हिस्सा तो सरकार के पूल में चला जाता है, 30 फीसदी बोर्ड ले लेता है और बाकी मार्किट कमेटी के पास सिर्फ 10 फीसदी बचता है जिसे वह

अपने काम में ला सकती है, लेकिन इस पैसे से कमेटी का सारा लोकल काम नहीं चल सकता। इसलिये मैं इस बारे में यह सुझाव देना चाहता हूँ कि बोर्ड को जो तीस फीसदी हिस्सा जाता है, उसे घटा कर बीस फीसदी कर दिया जाये और यह दस फीसदी लेकर मार्किट कमेटियों को दे दिया जाये, जिससे उनके पास बीस फीसदी हो जाये ताकि कमेटियाँ अपने लोकल काम ठीक ढंग से कर सकें। इसके साथ मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ये जो तीन टैक्स चल रहे हैं, प्रापर्टी टैक्स, हाउस टैक्स और प्रोफ़ै इनल टैक्स इनके बारे में भी सोचा जाये, और इनके लगाने के ढंग को रिवाइज किया जाये। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि जिस आमदनी एक हजार रुपये है उस पर यह नहीं लगने चाहिए, क्योंकि आजकल मंहगाई के जमाने में पांच सात सौ और एक हजार की आमदनी कोई मायने नहीं रखती इसलिये इस आमदनी वाले आदमी पर यह तीनों टैक्स अगर लगा दिये जाये, तो यह ज्यादाती वाली बात होगी, क्योंकि इतनी आमदनी में तो आजकल गुजारा नहीं होता। इसके अलावा मेरा इस बारे में यह सुझाव है कि इन तीनों टैक्सों को एक ही कर दिया जाये। अगर किसी वजह से यह तीन एक नहीं हो सकते, तो कम से कम यह कर दिया जाये, कि इनके लगाने के लिये एक हजार रुपये की आमदनी की लिमिट रख दी जाये। अब मैं कुछ बातें अपने हल्का के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ।

मेरी अर्ज यह है कि हमारी नरवाना की कमेटी को माली सहायता दी जाये क्योंकि वह बहुत माली तंगी मे है। दूसरी बात यह है कि बेलरखा माईनर जो हे वह अम्बरेसर गांव तक बना हुआ है और उससे आगे बताना छोड़ दिया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि उसे आगे बेलरखा गांव तक ऐक्सटैंड कर दिया जाये। यह फासला तो दो तीन किलोमीटर का ही है, इसलिये इसे अगर आगे बेलरखा तक बढ़ा दिया जाये, तो बहुत सारे गांव को फायदा हो सकता है और उनको पानी मिल सकता है। इसके अलावा बेलरखा गांव मे मवे ियों के लिये पानी पीने के लिये कोई जगह नही है, कोई घाट नही है, इसलिये मेरी प्रार्थना है, बरवाला लिंग नहर पर एक मवे ियों के लिये घाट बनाया जाये। इस वक्त घनौरी से लेकर नरवाना तक कोई घाट नही बना है। पानी पीने की बात तो अलग है, अगर उसमे कोई मवे ि गिर जाये, तो उसे निकालना मु ि कल हो जाता है। घाट के बना देने से एक तो दो तीन गांव के मवे ियों के लिये पानी पीने की सहूलियत मिल जायेगी, दूसरे और कोई मवे ि गिर जाए, तो उसे बाहर निकालने मे आसानी हो जायेगी। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हरिपुरा माइनरको घनौरी तक बनाया जाये। एक अर्ज और करता हूं कि बरवाला लिंग नहर पर एक माइनर बेलरखा मे या इससे पीछे निकाल दिया जाये, क्योकिहमारे 10-15 गांव को फायदा पहुंच सकता है। सिरसा ब्रांच और बरवाला ब्रांच दोनों के हैड जो बदनपुर गांव मे है, फतेहाबाद डिवीजन मे पड़ते है, और वह हमारे सारा माइनर को पूरा पानी नही देते। इस लिये मेरी अर्ज कि है इनके हैड

फतेहाबाद से नरवाना को तब्दील किये जाये। इस बार मे ऐक्स.ई. ऐन. को केस भेजा हुआ है और मै इरीगे ान मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि वह इसे जल्दी करवाने की कृपा करें। इसके नरवाना डिवीजन एरिया के 18 गांव ऐसे है, जो फतेहाबाद कैनाल डिवीजन मे है। इस नरवाना तहसील के गांवो को बहुत तकलीफ होती है इसलिये मेरी यह अर्ज है कि इन गांवों को नरवाना डिवीजन मे तबदील कर दिया जाये और यह पहले भी नरवाना डिवीजन मे हुआ करते थे। खारा माइनर का हैड बहुत पुराना बना है और उसे रिपेअर करने की बहुत जरूरत है। इसके साथ ही ढाबी पुल जो घमतान माइनर पर है, उसकी एप्रोच को भी रिपेअर किया जाये। इसके साथ ही खरल गांव में लोगों ने मवे ि ायों के हस्पताल के लिये काफी पैसा लगाकर बिल्डिंग बनाई हुई है, तो मेरी अर्ज है कि उस मे मवे ि ायों के लिये अस्पताल खोलने की कृपा की जाये। अब मैं कुछ रोड़ज के बारे मे सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। नरवाना टोहाना रोड जो है वह कई साल से मंजूर हुई है, और कालां गांव तक बन चुकी है, बीच मे सिर्फ तीन किलोमीटर का गेप रहता है, उसे पूरा किया जाये, ताकि वहां के लोगों को सुविधा मिल सके, क्योंकि इस वक्त लोगों को टोहाना जाने के लिये 15 मीन का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। एक दाता सिंह वाला कलायत रोड़ है, जो काफी बन चुकी है, लेकिन सिर्फ तीन छोटे छोटे गैप बीच मे बनने बाकी है, उनको बना दिया जाये, ताकि लोगो को आराम मिले। एक गुरथली नरवाना रोड़ है, जिस पर सोलिंग हो चुकी है, मैटीरियल भी उस पर पड़ा है,

इसलिये उसे जल्दी पक्का किया जाये। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) यह तो हुई रोड़ज की बात। अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे नरवाना मे ऐ विमैन कालेज है, उसके लिये ग्रांट के लिये हमारी मार्किट कमेटी ने एक लाख रूपया रखा है और केस गवर्नमेंट की स्वीकृति के लिये भेजा हुआ है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि वह ग्रांट मंजर करने की कृपा करें ताकि काम ठीक हो। इन भाब्दों के साथ मैं आपका भुक्रिया अदा करता हुआ अपना स्थान लेता हूं और जो बजट पे । किया गया है, उसकी ताईद करता हूं और फाईनैस मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बगैर टैक्स लगाए बजट पे । किया है।

(इस समय कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

उपाध्यक्षा: श्री धजा राम।

श्री धजा राम (सफीदो): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं मैं सबसे पहले आपका भुक्रियां अदा करता हूं कि आपने इतने मैंबर साहिबान खड़े होने के बावजद मुझे बोलने के लिये टाईम दिया।

उपाध्यक्षा: मैं यह ख्याल रखती हूं कि जो पीछे वाले है अक्सर उनको टाईम नहीं मिलता है, इसलिये मैंने आपको call upon किया है।

श्री धजा राम: मैं कई आइटम्ज पर बोलना चाहता हूं इसलिये मुझे जरा टाईम खुला देने की कृपा करें, मैं चाहता था इस वक्त चौधरी दल सिंह जी यहां पर होते लेकिन बदकिस्मती कि वह यहां नहीं है और वाक आउट कर गये हुए है (विघ्न) कोई बात नहीं, अगर यहां होते तो जरा मजा होता। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मित्तल साहब ने जो यह बजट पे किया है, यह बहुत अच्छे ढंग का है और मैं तो कहता हूं कि उन्होंने अपनी काबलियत का अच्छा सबूत दिया है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को ठीक ढंग से फंडज प्रोवाइड किये है। सबसे पहले मे फ़ैमिली प्लानिंग के बारे मे अर्ज करना चाहता हूं। आज हमारा दे आ बड़े नाजुक दौर मे से गुजर रहा है। मैं मानता हूं कि क्या खेती और क्या इंडस्ट्री, सब मे पैदावार बढ़ी है।

इसमे कोई भाक नहीं है, नेकिन जितनी असलियत कोमोडिटीज है, डेली रूटीन की डिमांड है, उसको हम मीट आउट नहीं कर सकते। वैसे बजट मे फ़ैमिली प्लानिंग के बारे मे ही रिक्वैस्ट हे कि इसके लिये जब तक कोई स्पैसिफिक लैजिस्लेशन नहीं लाया जाता, तब तक दे आ की बढ़ती हुई जनसंख्या नहीं घटेगी। इस तरह से अगर आबादी बढ़ती रहेगी, तो एक दिन आएगा कि यह एक बहुत बड़ी प्रोब्लम बन जायेगी। सरकारी आंकड़ों का जहां तक ताल्लुक है, 1901 मे जनसंख्या पौने 24 करोड़ थी। इस तरह 1971 की सेंसिज के मुताबिक पौने 55 करोड़ तक बढ़ी और आज जो साल चल रहा है, 1975 इसमे

लगभग 60 करोड़ के करीब है। इस तरह से अगर आबादी बढ़ती रही, तो सन 2000 तक मेरे ख्याल में एक अरब से ज्यादा आबादी ऐक्सीड कर जायेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि बढ़ती हुई आबादी को रोकने के उपाय किये जाये। वैसे सरकार ने इस दिशा में काफी कुछ किया है। फैमिली प्लानिंग अच्छी चीज है, लेकिन जब तक एक कानून नहीं बनाया जाता और जब तक कोई लैजिस्लेटिव नहीं लाया जाएगा तब तक आबादी बढ़ने से नहीं रुक सकती। फैमिली प्लानिंग में गरीब आदमियों को पकड़ते हैं कि नसबंदी करवाओं। वे करवा लेते हैं, लेकिन यह हर एक आदमी के लिये चाहे वह किसान है, चाहे कारखानेदार है, सब के लिये एक जैसा कानून बनाना चाहिए। अगर कानून नहीं बन सकता, तो मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि वे दिन दूर नहीं जब लोगों को रहने के लिये मकान नहीं मिलेगा, खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा और पहनने के लिये कपड़ा नहीं मिलेगा। इसलिये मैं गुजरात सरकार को कौंगु कि जहां हरियाणा सरकार दूसरे कामों में पहल कर रही है, ट्रांसपोर्ट क्या, रोडज क्या, गांव गांव में इलैक्ट्रिसिटी क्या, वहां बढ़ती हुई आबादी की तरफ भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम करके पहल करे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजरात सरकार को कौंगु कि जहां उन्होंने इन चीजों में पहल की है, वहां इस तरफ भी ध्यान दे। मेरा ख्याल है कि हरियाणा सरकार की तरफ से सबसे पहले कानून बनेगा। स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को कंसीडर करके लैजिस्लेटिव लाए। यह देश की तरक्की के लिये, राष्ट्र की मजबूती के लिये अच्छा कदम है।

दूसरी बात मैं ऐग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहता हूँ ।
सदन के बहुत से भाईयों ने ऐग्रीकल्चर के बारे में, किसानों के
बारे में, बिजली के बारे में बहुत सी बातें की। यह ठीक है, अपने
अपने सुझाव होते हैं। मेरा ख्याल यह है कि मित्तल साहब ने जो
बजट पेश किया है, इससे अच्छा हो नहीं सकता, मैंने इसको
अच्छी तरह पढ़ा है। खेतीबाड़ी और पावर एंड इरीगेशन के लिये
जो फण्डज इस बजट में प्रोवाइड किये गये हैं वे बिल्कुल सही हैं।
मेरे ख्याल में आप किसी भी स्टेट का बजट पढ़ें, इससे बढ़िया
बजट आप किसी स्टेट का देख नहीं सकेंगे। जो भाई इसको
क्रिटिसाइज करते हैं, वे आदत से लाचार हैं। मेरे ख्याल में
हरियाणा सरकार और चौधरी बंसी लाल को, किसान को जितना
ख्याल है, उतना किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को हनी हो
सकता। ध्यान होना भी चाहिए, क्योंकि वे खुद किसान हैं, इनसे
ज्यादा किसान के बारे में कौन सोच सकता है ? इरीगेशन में
जितनी तरक्की हुई है, वह सब जानते हैं, सरकारी आंकड़े हैं और
लोगों को पता है कि ट्यूबवैल के कितने कुनैवेंशन मिले हैं।
सरकारी आंकड़े हैं, मैं इनको रिपीट नहीं करना चाहता, अगर
रिपीट करूँ, तो समय लगेगा। मेरा ख्याल है कि इरीगेशन और
पावर में स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड ने जो काम किया है वह
सराहनीय है। इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब मैं
अपने हलके की तकलीफ आपके सामने रखना चाहता हूँ। डिप्टी
स्पीकर साहिबा, मेरा हलका कांग्रेस का हलका है, लेकिन हमारी
यह बदकिस्मती रही है कि हम गुलामों के गुलाम रहे हैं। पहले

अंग्रेजों के गुलाम रहे और फिर राजे महाराजाओं के गुलाम रहे। हमें पता है। जिस वक्त महाराज जींद, संगरूर से दौरे पर इस इलाके में आते थे, तो हमारे हरिजन भाई, किसान भाई, दुकानदार, नाई, धोबी सब के सब फ्री काम करते थे, हमें यह अच्छी तरह से मालूम है। इस इलाके की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। पिछले 6 सालों में, चौधरी बंसी लाल जी पहले चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने सफीदों के हलके की तरफ ध्यान दिया है। डिवलपमेंट हुई है, लेकिन फिर भी मेरी उनसे गुजारि है कि सफीदों का इलाका, खास तौर से जींद डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि यह इलाका गुलामों का गुलाम रहा है, इसको हरियाणा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बराबर लाया जाये। महेंद्रगढ़ भिवानी, हिसार और गुड़गांव जिलों में जो फैमिलिटीज दी जाती है, वही फैमिलिटीज जींद डिस्ट्रिक्ट को भी दी जानी चाहिए, क्योंकि जींद एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, इसकी जितनी तरक्की होनी चाहिए वह नहीं हुई। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी सरकार से गुजारि है कि जींद डिस्ट्रिक्ट को अगर प्रायोरिटी दे, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ एक माइनर है, जिनके बारे में खास तौर पर कहना चाहता हूँ। पानी किसान के लिये एक अहम चीज है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान मेहनत करता है, वैसे तो सारे हरियाणा का किसान मेहनती होता है, दौलता साहब, भायद इस बात को माईड करेंगे। रोहतक जिले के लोग बहुत बहादुर हैं, काम करते हैं, मेहनती भी हैं, लेकिन उनमें एक कमजोरी है कि

उनकी औरते खेत मे काम करती है और जो गांव के आदमी है, वे ता 1 खेलते रहते है। इसी तरह से दूसरे डिस्ट्रिक्टस है, भायद मित्तल साहब और सी.एम. साहब यह बात महसूस न करे। वहां साधन न होने की वजह से डैजर्टिड ऐरिया है, पानी लगता नहीं है। इस सिलसिले मे मै ऐ देहाती मिसाल देना चाहता हूं। एक बागड़ी ने ईख बो रखा थां जब ईख पेलने के लिये कोहलू चला तो 60 घरों का इकट्ठा कोहलू चला। उस कोहलू मे बागड़ी की बारी पहले नम्बर पर आ गई। पहले नम्बर पर आने से उसको 100 मन गुड़ आ गया उसके पास एक किल्ला ईख था, वह सारा खत्म हो गया, लेकिन दूसरी बार बारी नहीं आई। उसने चौधरन से कहा कि मटो खेती ईख की करे, लेकिन बाद मे उसकी बारी नहीं आई और दूसरे किसानों की बारी आती रही। वह फिर चौधरन से कहता है कि मटी ईख की खेती कुछ नहीं, इसकी आगड़ी अच्छी है, पाछड़ी कुछ नहीं है। —(हंसी)— मैं कह रहा था कि जींद डिस्ट्रिक्ट का किसान बहुत मेहनती है, वैसे तो सारे हरियाणा का किसान मेहनती है, लेकिन जींद डिस्ट्रिक्ट के किसान मे यह खास खूबी है कि वह अकेली औरतो को खेत मे नहीं भेजतां आदमी पहले खेत मे काम करने के लिये जाते है। औरते तो बैलों के लिये चारा वगैरा या खाना लेकर जाती है तो कहने का मतलब यह है कि उनको अगाड़ी और पछाड़ी का पता है। मेरे हलके मे दो माइनर का निकलना जरूरी है। एक गंगोली माइनर के साथ होि गियारपुरा, कलोपी, खर्कगागड़, कालवा, हावड़ा, भागखेड़ा, और गंगोली गांव को पानी लगेगा। इन गांवों का तकरीबन 10 हजार

एकड़ का एरा रकबा है, जो बिल्कुल ड्राई है। अगर किसी दोस्त को यकीन न हो, तो मेरे हल्के में आये और अपनी आंखों से देख ले। किसान मेहनत करता है, सुबह से भाम तक मेहनत करता है, अगर उसको पानी न मिले, तो उसका दिल टूट जाता है। यह आपको अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से किसान काम कर रहा है। लोन लेकर वह अपनी काम चला रहा है। उसको सरकार ने फ़ैसिलिटी दी है, इसमें कोई भाक नहीं है। लेकिन उस फ़ैसिलिटीज के बावजूद भी एक किसान अपने खेत में यदि बीज बो देता है और बाद में उसको पानी न मिले, तो पैदावार किस तरह बढ़ सकती है? इससे तो वह कर्ज के अंदर दब जाता है। इसलिये किसान को पानी दिया जाना बहुत जरूरी है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा मैंने पहले कहा मेरे हल्के में दो माईनर्ज निकाली जाये। एक तो रोहड़ माईनर है, जो कि जींद नं. 1 में से निम्नाबाद गांव के पास से निकलकर मिलखपुर, थो मिलखपुर से होती हुई रोहड़ तक है। इसे कृपा जल्दी से जल्दी बनाया जाये, क्योंकि इसके बिना काफी रकबा पानी के बिना पड़ा है। अगर यह बन जाये, तो इससे एक तो पैदावार बढ़ेगी, और दूसरे किसान खुहाल होगा। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

स्पीकर साहब, पिछले दिनों गुप्ता साहब सफीदों गए थे। इन्होंने कहा था अगर गांव के लोग जमीन दे, तो हमें नहर निकालने में कोई ऐतराज नहीं, हम गौर कर सकते हैं। मैं उन्हें, आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि लोग वहां जमीन देने के लिये

तैयार है। इसी तरह से स्पीकर सहब, दूसरी माईनर गंगोली माईनर है। यह जींद नं. 3 मे से आर.डी. 50940 लैफ्ट के पास से निकलेगी और इस सभी गांवों हो गिरपुरा, कालावती, खर्कगागड़ा, हाडवा, भागखेड़ा, कालवा और गंगोली भामिल होंगे। इससे भी आठ हजार एकड़ के करीब रकबा सैराब होगा, और जिसका परिणाम यह होगा कि पैदावार बढ़ेगी और किसान खुहाल होगा, और जिसका परिणाम यह होगा कि पैदावार बढ़ेगी और किसान खुहाल होगा। इसके बारे में भी लोगों ने यह कहा है कि हम फ्री जमीन देने के लिये तैयार है। जहां से सरकार चाहे, वहां से माइनर निकाली जा सकती है। यहां तक लोग को आप्रेशन देने के लिये तैयार है। तो स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत सरकार से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि इन माइनरज की तरफ सरकार जरूर ध्यान दे, क्योंकि आज बढ़ती हुई जनसंख्या, के लिये अनाज की बहुत जरूरत है। इसमें कोई भाक नही कि हमारी हरियाणा सरकार ने पिछले सालों में अनाज की काफी पैदावार बढ़ाई है। पहले हम जहां सेंट्रल पूल से अनाज लेते थे, वहां आज हम लाखों टन के करीब अनाज सेंट्रल पूल में देते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं और मैं इन्हें रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें कोई भाक भुबह की बात नहीं कि हरियाणा के किसान ने खेती बाड़ी करने वाले लोगों को और हरियाणा की सरकार ने खेती के मामले में तरक्की की है। लेकिन फिर भी किसान को अगर पूरा पानी दिया जाये, तो पैदावार और भी ज्यादा हो सकती है। सारे हरियाणा के अन्दर आज किसान सब

नही कर सकता। आज वह उतावला है, आज किसान को और भी स्पीडिली जितने भी ज्यादा से ज्यादा साधन दे सके उतने ही मैं कम समझता हूँ।

स्पीकर साहब, चूंकि गुप्ता साहब अब हाउस में आ गए हैं, इसलिये इनमें मैं एक और बात आपकी मारफत कहना हूँ। मेरे इलाके में करीब 45 ट्यूबवैल्ज एम.आई.टी.सी. ले लगाए हैं। स्पीकर साहब, यह बात मैंने गुप्ता साहब को जब ये 4 अप्रैल, 1974 को सफ़ीदों गए थे, तब भी कही थी। चट्टा साहब से भी मैंने गुजारि 1 की थी और मेरा ख्याल है सी.एम. साहब के नोटिस में भी, जब ये भी पिछले दिनों वहां गये थे, लोग इस बात को लाए थे। दिक्कत यह है, स्पीकर साहब, कि वे जो सरकारी ट्यूबवैल्ज हैं, उनकी बाराबंदी बड़े गलत तरीके से टाईमिंग के हिसाब से बनाई गई है। बिजल आपको पता है रात बारह बजे आती है और 6 घंटे या 8 घंटे ही केवल रहती है। अब आप ही बताएं कि इससे सब आदमियों को कैसे पानी मिल सकता है। जिसकी बारी सुबह आठ बजे से लेकर रात बारह बजे तक पड़ती है, वह तो रोज ही पानी के बगैर रहा जाता है और जिसकी बारी रात बारह बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक यानी जब तक बिजली रहती है, पड़ती है, उनको रोज पानी मिल जाता है। इसलिये मेरी गुजारि 1 है कि इस बाराबंदी को चेंज करवाया जाये और जिन घंटों में बिजली मिलती है उन्हीं आवर्ज के मुताबिक किसानों को बिजली दी जाये। स्पीकर साहब सरकार तो पालिसी अच्छी बनाती है, किसान को

खुहाल बनाने के लिये, किसान के ऊपर उठाने के लिये, लेकिन जो नीचे छोटे मुलाजिम है, वे सरकार को कोआप्रेट हनी करते, वे किसान की मजबूरी को नहीं समझते। इसलिये मेरी आपके द्वारा सरकार से यह भी गुजारिा है कि ये जो छोटे लेवल के मुलाजिम है, इसके विद्ध सख्ती के कदम उठाने की जरूरत है। अब जमाना तेजी से चल रहा है। सरकार भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसलिये कर्मचारियों को भी तेजी से कदम बढ़ाने चाहिए।

स्पीकर साहिब, जिस वक्त हरियाणा वजूद मे आया, हमारे साथी स्टेट के भाई यह कहते थे कि हरियाणा छोटी स्टेट है, हरियाणा एक बैकवर्ड स्टेट है, हरियाणा एक पिछड़ी हुई स्टेट है और हरियाणा ऊपर नहीं उठ सकेगा। आज इस संबंध मे हमें बहुत कहने की जरूरत है कि हरियाणा जो फर्स्ट नवम्बर, 1966 को हिन्दुस्तान के नक्शे पर एक रोजानी बन कर आया था, वह आज हिन्दुस्तान मे कई मामलों मे कई इतूज मे, डिवैल्पमेंट के हिसाब से सबसे पहली स्टेट है। यह सब, स्पीकर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से है। हमें सौभाग्य से एक अच्छे चीफ मिनिस्टर मिले है। वे बहुत काम करने वाले है और दिन रात काम करने वाले है। जैसा दौलता साहबन ने कहा वे तो सोते भी बहुत कम है। रात को दो दो तीन तीन बजे तक कभी चीफ इंजिनियर को बुलाते है, कभी मिश्रा साहब को बुलाते है, ओर कभी किसी को बुलाते है। जिस आदमी को इतनी लग्न हो, जो किसान के लिये, हरिजन के लिये, के लिये, बैकवर्ड क्लासिज

के लिये, छोटे दुकानदार के लिये, इंडस्ट्रीयलिस्टस के लिये यानी तमाम हरियाणा की डिवैलपमेंट के रात दिन सोचता रहता है, उसके बारे में या हरियाणा स्टेट में अपोजी उन के भाई किस मुंह से कहते हैं कि हरियाणा में कुछ नहीं हो रहा ? बड़े कमाल की बात है। अच्छा होता वे भाई हाउस में होते। उनके सामने अगर मैं ये बातें कहता तो बड़ा मजा आता। स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि वे भाई 22-23 साल तक पावर में रहे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। एक मजेदार बात, स्पीकर साहब, मैं और बताना चाहता है। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा इस हाउस में नोटिस में यह लाना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के सबसे पहले डिफैक्टर चौधरी दल सिंह है, जिन्होंने सन् 1952 में पैप्सू में सबसे पहले कांग्रेस छोड़ी और और भायद दो दिन के बाद रात को जब ये बाबू दया कृष्ण के पास गये तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत गलती की। उसी वक्त रात को ये कर्नल रघुबीर सिंह जी की कोठी पर गये, जो कि उस समय चीफ मिनिस्टर होते थे, उनके इन्होंने माफी मांगी.....

श्री अध्यक्ष: तो स्पीकर साहब, यह नाम वाली बात मैं विदड़ा करता हूँ। स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह था कि यह कहना कि हरियाणा में कुछ नहीं हुआ, यह एक बेबुनियाद बात है और इस तरह की बातें सिर्फ पीछे गैलरी में बैठे हुए लोगों को दिखाने के लिये बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है। बातें हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी तरह गलत बातें नहीं करना चाहते।

इसके बाद स्पीकर साहब, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। यहां नहरों के बारे में बात आई। एक भाई ने कहा कि मैं जानता हूँ नहरें कहा कि मैं जानता हूँ नहरे कहां निकली, कैसे निकली और किस इलाके में निकली। स्पीकर साहब, खास कर मेरे अपने हल्के के बारे में है। हम तो चीफ मिनिस्टर साहब के आभानी हैं। मेरे हल्के सफ़ीदों में यह पोजी तन थी कि हर साल फलडज आते थे। मुझे याद है कि ड्रेन नं. 8 से सारे पंजाब और यू.पी. का पानी वहां आता था और रोहतक तक के सारे इलाके में लाखों और करोड़ों रुपये की फसल बरबाद हो जाती थी। किसान का आर्थिक ढांचा बिगड़ चुका था, लेकिन पिछले 6 साल से हमें कुछ राहत मिली है। अगर इन हालात में इंदिरा गांधी कैनल मेरे हल्के में अंटा गांव के पास से निकाल कर चौधरी बंसी लाल जी ने मरते हुए लोगों को तबाही से बचाया है और जिन इलाकों को पानी नहीं मिलता था, उनको पानी दिया है तो क्या जुल्म किया है? क्या वे हिन्दुस्तान के रहने वाले नहीं? क्या वे हमारे भाई नहीं? उनका हक नहीं है? यह तो इंसानियत के नाते भी ऐसे लोगों की मदद करना हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है। स्पीकर साहब, मेरे भाई जी कि एक आनरेबल मेंबर है, जो कि एक पुराने पार्लियामैंटरियन है, वे अगर इस तरह की बातें कहते हैं, तो बहुत गलत बात है। मैं तो उनके मुकाबले में बहुत जुनियर हूँ, पहली बार हाउस में आया हूँ, लेकिन फिर कहना चाहता हूँ कि एक आनरेबल मेंबर को हर बात सोच समझ कर करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब अकेले भिवानी के, महेन्द्रगढ़ के नहीं हैं, वे तो

तमाम स्टेट है। चौधरी बंसी लाल का फर्ज है कि चाहे हिसार हो, गुड़गांव हो, रोहतक हो, जींद हो, अम्बाला हो या चाहे करनाल हो, सबकों एक नजर से देखें। वे ऐसा कर रहे है। इसमे कोई भाक की बात नही है। अगर चौधरी दल सिंह जी या अपोजी इन के दूसरे भाई तैयार न हो, देखने को तैयार न हो, तो इसका मेरे पास कोई इलाज नही है।

अब मैं हैल्थ के बारे मे अर्ज करना चाहता हूं। हैल्थ के मामले मे हरियाणा स्टेट ने काफी तरक्की की है। इस बजट मे भी मित्तल साहब ने फण्डज प्रोवाइड किये है, उनमे कोई भाको भुबहा नही हैं मैं आपकी मार्फत अपने हल्के के बारे मे अर्ज करना चाहता हूं। सफीदों का जो हास्पिटल है, वह 25 बैडस का है। वह हास्पिटल सरकारी कागजात मे तो 25 का है, इसमे कोई भाक वाली बात हनी है, लेकिन उसकी बिल्डिंग तो प्राईमरी हैल्थ सेंटर के बराबर भी नही है। मेरी गुजारि है कि जो सफीदों का सिविल हास्पिटल है, उसकी बिल्डिंग को ऐक्सटेंड किया जाये और वहां पर और कमरे बनवाए जायें। वहां बरामदे मे मरीज चारपाई डाले रहते है। मैं भी वहां कभी कभी जाता हूं, तो हमें बहुत महसूस होता है, भार्म आती है कि सर्दी के मौसम मे, पोह के जाड़े मे बीमार बरामदे मे चारपाई डाले रहते है। कितना गलत बात है। इसी तरह से गर्मी के मौसम मे ज्येष्ठ के महीने मे बरामदे मे चारपाई डाले रहते है ? मेरा कहने का मतलब यह है कि इसकी बिल्डिंग के लिये सरकार जल्दी जल्दी फंडज प्रोवाइड

करे। इसी तरह से कालवा प्राइमरी हैल्थ सेंटर है। वह डिस्पेंसरी की बिल्डिंग में है। वहां पर बिल्डिंग के लिये जमीन दी जा चुकी है तो उसके लिये भी मेरी गुजारि है कि जल्द से जल्द फण्डज दिये जायें और वह बिल्डिंग बनवाई जाये। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में तो प्राइमरी हैल्थ सेंटर केवल कालवा ही है वह कागजात में तो प्राइमरी हैल्थ सेंटर हैं उसके केवल दो कमरे हैं, डिस्पेंसरी की बिल्डिंग में है, जल्द इसी साल में उस पर वर्क स्टार्ट किया गये, तो बड़ी अच्छी बात होगी। स्पीकर साहब, मैं समय थोड़ा ही लेने की कोशिश करूंगा। एक दो बातें हैं, उनके बारे में अर्ज करना चाहता हूँ।

हरियाणा में बहुत सड़कें बनी हैं, कोई भाक भुबह नहीं। आज हरियाणा में गांव गांव में बसें जाती हैं आज हमें महसूस भी होता है कि यह सरकार लोगों की भलाई के लिये काम कर रही है। यह तारीफ करने की बात है। तारीफ हम करते हैं, लेकिन अपोजी उन को अच्छी नहीं लगती। वे कहते हैं कि सड़कें नहीं बनी। मैं तो यह कहता हूँ कि जब हम चण्डीगढ़ से चले, पंजाब की हद पार करने के बाद जब हम हरियाणा में दाखिल होते हैं, तो सड़कों दोनों तरफ दरख्त साईड पर ऐसे लगते हैं, जैसे दुल्हन को सजाया गया हो। अगर फिर भी अपोजी उन के भाई क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि यह गलत बात है। स्पीकर साहब, मैं अपने हल्के की तीन सड़कों के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। एक सड़क सफीदों से उडवाड़ा वाया नीमनावाद

जाती है। यह सात मील लम्बी हैं वहां के लोगों की तब से मांग चली आ रही है, जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है, जब से लोगो ने वोट मोंगने भुरू किये है। इस सड़क को बनवाया जाना बहुत जरूरी है। उकने पास बड़ी दिक्कत होती है। वहां कुछ मेरे सिख भाई भी है, जो दूध बेचने का काम करते है। वे दूध बेचने के बड़े भाौकीन है, बड़े अच्छे मेहनती किसान है। तो मेरी गुजारि 1 है कि उस सड़क को बनवाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह स्टेट की तरक्की की बात है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी सड़क सफीदों से मूसलाना वाया ठीडाखेड़ी, बरड़ोद, बसनी और खातला होती हुई जाती है। इस सड़क सफीदो का बनवाया जाना भी बहुत जरूरी है। तीसरी सड़क जामनी से पीलुखेड़ा की है। पीलुखेड़े मे मंडी भी है। सैंट्रल प्लेस है। मैंने यहां हाउस मे पीलुखेड़ा मंडी का बार बार कहा हैं भायद मेरे बारे मे यह सोचे कि गुलाटी साहब की तरह से उनको बहम हो गया है। मैं बार बार इसीलिये जोर दे रहा हूं कि पीलुखेड़ा मंडी के लिये यह बहुत ही जरूरी सड़क है। वहां पर जो व्यापारी बैठे है, उनको बड़ी दिक्कत है। अगर व्यापानी को एक पैसे का भी नुक्सान होता हो, तो उसको बहुत महसूस होता है। यह बहुत जरूरी टुकड़ा है। मुि कल से दो मील का टुकड़ा है। सरकार के लिये दो तीन लाख रूपया कोई बड़ी बात नही है। चीफ मिनिस्टर साहब सफीदों गये थे, तो वहां की गांव की पंचायत ने और व्यापारियों ने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा था । चीफ मिनिस्टर साहब वहां हां करके आए थे कि इस सड़क को बना दिया जायेगा। तो मेरी गुजारि 1

है और पंडित जी भी हाउस में बैठे हुए हैं अगर चीफ मिनिस्टर वहां हां करके आये हैं, तो इस बात का पता करें कि इस सड़क को क्यों नहीं बनवाया जा रहा है ? यह वहां के लोगों की भलाई और तरक्की के लिये बहुत ही जरूरी सड़क है ।

इंडस्ट्री की भी बात यहां आई । जैसे तो बाबू गुलाब सिंह जी काफी कह गए हैं । मैं भी एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष: आप वाइड अप करें । आप अपने प्वायंट्स रख दें ।

श्री धजा राम: मैं यहां पर बैंक्स के बारे में कहना चाहता हूं । स्पीकर साहब, जैसे तो यहां हाउस में गोबर गैस प्लांट की बात आई है, भैंसों के लोन की भी बात आई है, ट्रैक्टर के लोन की भी बात आई है, ट्यूबवैल्ज लोन की भी बात आई है, लेकिन जो गोबर गैस प्लांट्स के लिये बैंक्स कर्जा देते हैं, उसके बारे में सरकार के नोटिस में कुछेक बातें लाना चाहता हूं । ये बैंक्स हैं, पंजाब नैशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सेंट्रल बैंक, ये बैंक लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करते इस बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि पता नहीं बैंक वालों को क्या तकलीफ है ? एक एक किसान के, हरिजन के दस दस चक्कर कटवाते हैं । तो मेरी गुजारिश है कि हरियाणा सरकार इन बैंक्स को अपने आप

या गवर्नमेंट आफ इंडिया के जरिये इंस्ट्रक्शन दे कि विद इन फोर या 10 डेज उनको कर्जा मिल जाये।

अब मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। गांव-गांव में पानी गया है इसमें कोई भाक-सुबह की बात नहीं हैं, लेकिन स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत सरकार के नोटिस में एक-दो बातें लाना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में मेरा असैम्बली क्वैशन भी था। मेरे हल्के के अन्दर 33 गांव ऐसे हैं जहां खारा पानी है, गहरा पानी है। अच्छे पानी के बगैर लोगों की सेहत खराब हो जाती है। सन् 1952 से आज तक 33 गांवों के अन्दर वाटर सप्लाई स्कीम नहीं बनायी गई है। मैं आपकी जरिए सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि पीने का पानी देना बहुत जरूरी है। जब पीने का पानी अच्छा नहीं मिलेगा तो इंसान की सेहत भी खराब हो जाएगी व न काम कर सकता है, न मेहनत कर सकता है। कम से कम कालवा, मुआना ये आठ-आठ हजार की आबादी के गांव हैं इनमें तो पानी का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। हाट ऐबराकला भी ऐसा ही है। इन गांवों को टाप-प्रायोरिटी दे कर जल्दी से जल्दी पानी का प्रबन्ध करवाया जाए।

अब एक आत हरिजनों के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। हरिजन निगम बनी। बड़ी अच्छी बात है। सरकार पैसा दे रही है भेड़-बकरियां पालने के लिए, सुअर पालने के लिए और जो चमड़े का कमा करते हैं। मैंने बजट को पढ़ा है लेकिन इसमें जो

फण्डज रखे गए हैं, वे कुछ कम रखे गए हैं मैं मितल साहब से गुजारि । करूंगा कि नैक्सट ईयर आप इस निगम को ज्यादा पैसा दें। यह भी हमारे समाज का हिस्सा है। अगर आप इस समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं तो इनकी सहायता करनी ही पड़ेगी। जिस प्रकार से भारीर का एक अंग कमजोर हो जाए तो वह पूरा पहलवान नहीं बन सकता, इसी तरह से अगर हम राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हरियाणा सरकार को उनके लिए ज्यादा फण्डज देने पड़ेंगे क्योंकि ये भी बड़े उतावले हैं।

इनको भी थोड़ा ऊपर उठाने की बात होनी चाहिए। इसके लिए अगर ज्यादा फण्डज रखे जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। (घंटी) स्पीकर साहब, वैसे तो मैं एक दो प्वायट्स पर और बोलना चाहता था लेकिन चूंकि आप चाहते हैं, मैं बैठ जाता हूं। आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mittal):

How much time would you allow me?

श्री अध्यक्ष: मितल साहब, देखिए यह डिमाण्ड् ज की डिस्कान दो दिन और चलेगी और डिमाण्ड्ज में कुछ सिलैक्टड डिमाण्ड्ज तो हैं नहीं, सारी डिमाण्ड्ज हैं तो वही जनरल डिस्कान जो बजट पर है, तकरीबन उसी नेचर की डिस्कान

डिमांडज पर होगी। आप उसके आखिर में जवाब देना पसन्द करेंगे या पहले?

Shri Ram Saran Chand Mital: Any time which you think proper.

अगर डिमांडज पर डिस्कान, जनरल डिस्कान के मुताबिक ही रखनी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं आखिर में ही जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: मेरे ख्याल में डिमांडज की डिस्कान इसी तरह चलती रहे और उसके आखिर में ही आप जवाब दे दें, तो ठीक है।

श्री राम सरन मित्तल: ठीक है जी।

श्रीमती लेखवती जैन(अम्बाला): जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत-2 भुक्तिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया। यह मैं जानती हूँ कि क्वै चन आवर मैं भी ओर दूसरे टाइम पर भी आप ही चेयर पर होते हैं। जब आप मुझे यहां चेयर पर बिठाते हैं, तो आपके आराम करने का टाइम होता है। जब मुझे कभी दो-चार मिनटके लिए बोलना होता है तो आपसे कह देती हूँ कि आप यहां चेयर पर आ जाएं। मैं इस बात के लिए भी आपका भुक्तिया अदा करती हूँ कि जहां पर आप सारे हाउस का ख्याल रखते हैं, वहां पर आप मेरा भी यानी डिप्टी स्पीकर का भी खास तौर से ख्याल रखते हैं। जनाब, आप यह भी

जानते ही है कि जब आप चेयर पर होते हैं और यहां पर किसी मसले पर डिस्कशन होती है तो आपका भी दिल बहुत चाहता होगा कि मैं भी हाउस के अन्दर कुछ न कुछ तो बोलूँ। ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने हल्के की बात कर लूँ। आप इतने आई-पार्वर्ड हैं कि अगर आप अपने हल्के के काम किसी को भी लिख दें तो वह बिना कहे ही अपने आप हो जायेंगे। दूसरी बात यह है कि मुझे इस बात की इजाजत है कि मैं आपको यहां पर बिठाकर यहां पर बोल सकती हूँ परन्तु आप अपने विचार मेरी तरह से हाउस के सामने नहीं कह सकते। यह बात अलग है कि आप किसी मौके पर कोई बात इसी चेयर से कह दें।

जनाब, आज जो हाउस के सामने बजट के उपर जनरल डिस्कशन है उस पर मैं सबसे पहले तो अपने फाईनैस मिनिस्टर साहब को बहुत-2 मुबारिकबाद देती हूँ कि उन्होंने हाउस के अन्दर बहुत अच्छा बजट पेश किया है सबसे बड़ी बात कहने के लिए यह है कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं है। हमारा यह बजट बेनाक डैफिसिअ बजट है, परन्तु मैं समझती हूँ कि डैफिसिट बजट का होना यह जाहिर करता है कि यह सरकार कितने ज्यादा काम करती है जनता ही से पैसा लेकर जनता ही के लिए खर्च करती है। यही नहीं, जनता से कितना पैसा लिया जायेगा, उससे भी ज्यादा पैसा खर्च करने के लिये यह सरकार तैयार है। यह सरकार जनता के लिए हर तरह से काम करने के लिए तैयार है और वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि हम यह

देखेंगे कि किसी तरह से भी जो बजट का डैफिसिट है, उसको हम पूरा करें। वह घाटा भी महज टैक्सेशन से नहीं गायद सैन्टर से रिक्वैस्ट करके हम अपने बजट के डैफिसिट को पूरा कर लें जनाब, जब यहां पर बजट के उपर बहस हो रही थी तो अपोजी इन की तरफ से इसका काफी क्विंटिफाइज किया गया। गवर्नमेंट की कई चीजों को इस तरह से जाहिर किया गया जैसे कि गवर्नमेंट कुछ काम ही नहीं करती। जनाब, मैंने जो आपसे समय लिया है वह महज इसलिये लिया है ताकि मैं अपने हल्के की एक-दो बातें आपके सामने हाउस में कह दूं। मेरे पास बैठने वाले अपोजी इन के साथी जब ऐसी बातें कहते हैं जिससे दिल को दुख होता है जो दिल के अन्दर जाकर चुभती है तो मेरा दिल यह चाहता है कि मैं भी इन्हे बताऊं कि आप बातें बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसके लिए एक तो समय चाहिये और दूसरी चलज जो है वह यह है कि हमारे मिनिस्टर साहिबान और हमारे जो ट्रेजरी बैन्चिज के मॅबरान हैं, वे उसका अच्छी तरह से मुह तोड़ जवाब दे देते हैं। जिस वक्त मैं यहां पर थी तो हमारे एक आनरेबल मॅबर ने हमारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को क्विंटिफाइज किया। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इरीगे इन एंड पावर मिनिस्टर साहब ने उसका बहुत काबलियत से जवाब दिया। उन्होंने इस तरह से जवाब दिया कि जैसे स्लेट पर जो उन्होंने काटे माटे खींचे थे वे स्लेट से धो दिये हो। यह बात नहीं है जैसे अपोजी इन वालों ने कहा कि बिजली बोर्ड ने काम नहीं किया है, बिजली बोर्ड ने तो बहुत सेवा की है। जब यहां पर यह कहा गया कि फलां प्रान्त

के अन्दर 10000 गांवों को बिजली दी गई और फलां प्रान्त के अन्दर 15000 गांवों को बिजली दी गई तो यह बात मुझे बहुत चुभी। उन्होंने यह नहीं कहा कि वहां पर कुल 50000 गांव थे और इसमें से 10000 को बिजली दे दी गई । उन्होंने यह नहीं बताया कि कुल कितने गांव थे। उन्हें यह चाहिये था, वे बताते कि इतने प्रान्तो के अन्दर सैंट परसैंट बिजली दे दी गई। उन्होंने बोलते हुये यह नहीं सोचा कि यह छोटा सा प्रान्त है और इसे जन्में हुये कुछ ही साल हुये है और हमने सबसे पहले गांवों में सैंट परसैंट बिजली दी है।। यह हमारे लिए फख की बात हैं इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें है जो यहां पर कही जाती हैं। मगर मैंने पहले ही आपसे यह रिक्वैस्ट की है कि मैं तो दो चार बातें आने हल्के की ही कहना चाहती हूं। आप जानते ही है कि कहने वाले तो कहेंगे ही क्योंकि मारने वाले के तो आप हाथ पकड़ सकते हो लेकिन कहने वाले की जुबान नहीं पकड़ सकते। सदन के अन्दर उन्हें आजादी है कि जो मर्जी कहें। चाहे वह गलत बात कहें चाहे किसी बात को किसी तरह से कहें। एक आनरेबल मैंबर ने तो यह भी कह दिया कि एजुके ान में भी भेदभाव है। वे यह तो कह सकते हैं कि एजुके ान ठीक नहीं है इस तरह की एजुके ान होनी चाहिए या इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, मगर यह कहना कि एजुके ान में भी भेदभाव हैं, ठीक नहीं है। मैं यह समझ नहीं सकीं कि क्या अमीरों के लिए कोई अलग कालेज है और गरीबों के लिए कोई अलग कालेज है ? मैं तो इतना जानती हूं कि गरीबों को और हरिजनों को हमारे एजुके ान डिपार्टमेंट या

हमारी सरकार खास रियायतें देती हैं। उनके लिए वजीफे हैं, उनके लिए दूसरी रियायतें हैं। इतना ही मैं जानती हूँ। इससे ज्यादा मैं आपके सामने नहीं कह सकती क्योंकि यदि मैं इन बातों को कहने लगी तो फिर भायद मेरे हल्के की बातें रह जाएं। यहां पर एक और चीज कही गई जो मुझे बहुत चुभी है। इसमें कोई भाक की बात नहीं है कि हमारे दे 1 की 80 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि सारा हमारा जो दे 1 है, वह का तकारों पर निर्भर है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा दे 1 कृषि प्रधान दे 1 है। हम कृषि के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए हमारी सरकार की ज्यादा से ज्यादा अटैन्शन इस ओर होनी चाहिए। हम यह नहीं कह सकते कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे देहातों को या हमारे कृषि के का तकारों को, जमींदारों को, बिलकुल इग्नोर कर दिया है और उनको कुछ दे ही नहीं रही है। मैं तो यह समझती हूँ कि अंग्रेजों के जमाने में का तकारों की क्या हालत थी और आज के जमाने में क्या हालत है यह देख ले। इस बात को भी छोड़िये। मैं यह कहूंगी कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है इनके आने से पहले या पंजाब के साथ, हमारी क्या हालत थी और आज क्या हालत है इस चीज का मुकाबला करें तो मालूम होगा कि इस सरकार ने का तकारों को कितनी रियायतें दी है। हमारी सरकार जमींदारों को का फी सहायता दे रही है और इसने ग्रीन रैवोल्यूशन लाने के लिए हर तरह से एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। चाहे बीज है, खाद है या कुछ ओर है उनको सब चीजे दे रही

है। जब सब चीजों की मंहगाई है तो बे तक खाद की मंहगाई अखरती है मगर हम यह नहीं कह सकते कि उनको सहूलियतें नहीं दी जा रही है। सहूलियतें उनको बकायदा दी जा रही है। हमारे जा 'इरीगे ान ऐंड पावर मिनिस्टर है, उन्होंने यह कहा कि मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता था कि मैंने और चीजों के लिए सारी बिजली बन्द करके महज खेती के लिए जमींदारों को बिजली दी और ट्यूबवैलों से जमीन को पानी दिया? आप ही सोचिये इससे ज्यादा क्या हो सकता था कि बड़े-2 कारखानों को बन्द करके, इंडस्ट्री को बिजली न देकर ट्यूबवैलों को बिजली दी गई। मैं यह समझती हूँ कि यह एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारी गवर्नमेन्ट ने जमींदारों या कालतकारों के लिये की है जहां तक इंडस्ट्री को बिजली देने का ताल्लूक है इसके बारे में मेरा कहना यह है आखिरकार इंडस्ट्री को भी हमें बिजली देनी पडती है। इंडस्ट्री से जमींदार का उतना ही सम्बन्ध है जैसे कहा करते हैं कि चोली दामन का सम्बन्ध। इंडस्ट्री और जमींदार का सम्बन्ध भी ऐसा ही है। अगर इंडस्ट्री नहीं है तो जमींदार भी नहीं चल सकता। उसको अपने हल के लिए चीज चाहिये उसको अपने ट्रैक्टर के लिए चीज चाहिये उसको ट्रैक्टर चाहिये ओर चीजे चाहिये जोकि इंडस्ट्री से पूरी हो सकती है। हमारे देश के अन्दर गरीब हैं और हमारे देश के अन्दर मजदूर हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री नहीं है तो हमारा मजदूर कहां से पेट भरेगा? अभी जींद के अन्दर एक बड़ा कारखाना खोला गया है जो पशुओं के लिए चारा पैदा करेगा। जींद में जो बड़ी फैक्ट्री खोली गई है और

जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत रूपया लगाया है वह भी जमीदार की गाय और भैंस के लिए चारा बनाएगा। सरकार जो वाईट रेवोल्युशन चाहती है उसमें यह काफी मददगार सिद्ध होगा। जो जमीदार खेती से गुजारा नहीं कर सकते, वे गाय और भैंस से गुजारा कर सकेंगे। आज उस चारे का भाव 1.17 रूपये है। क्या कोई आनरेबल मैनबर बता सकता है कि इससे सस्ता चारा और क्या हो सकता है जो गाय और भैंस को दिया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि खल का भाव आजकल 1 या डेढ़ रूपये होगा और बिनौला का भाव दौ-पौने दो होगा, सूं का भाव तीन रूपये मेथी का भाव तीन रूपये चने का भाव तीन रूपये या ढाई रूपये होगा और गेंहूं का भाव 1.40 या 1.50 रूपये होगा। इस चारे से आज कौन सी सस्ती चीज मिल सकती है? मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस चारे का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिये। जिनको इस चारे की एंजेसी दी है, जो एजेंट है, उनको साधन दिये जाये ताकि वे अधिक से अधिक प्रचार कर सकें। अभी तक तो लोगों को मालुम भी नहीं है मुझे भी अभी आठ-दस दिन हुये है मालुम हुआ है और जब मैंने अपनी भैंस को डालना शुरू किया है तो वाकई दो किलो दूध बढ़ गया और किसी चीज के डालने के जरूरत ही नहीं हैं। दो-दो किलो उसको डाल दो। स्पीकर साहब मैं यह बातें कहते-कहते कहीं अपने हल्के की बात न भूल जाऊं। लेकिन क्या करूं हम अपनी आदत से मजबूर होते हैं, जब बोलने के लिए खड़े हो जाये तो दिल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बात कहें। स्पीकर साहब मैं किसी कंट्रॉवर्सी में नहीं पड़ना

चाहती। —(विधान) मैं दबी आवाज से एक बात कहना चाहती हूँ कि यहां पर कहा गया कि जमींदार की बात और अनाज पैदा करने वाले की करनी चाहिये। उनके लिये तो मैं ने सब बात कर दी कि इनको सहूलियत दी जाये , यह चीज उनके लिए की जाये। मैं एक जरूरी बात आपसे बताना चाहती हूँ कि आज की गवर्नमेंट जातपात में वि वास नहीं करती। आज चाहे बनियाहो, चाहे जमींदार हो और चाहे एक हरिजन हो, गवर्नमेंट सबको एक तरह से समझती है। आज वह जमाना नहीं जैसा कि अंग्रेज का जमाना था। अंग्रेजों के जमाने में मैं मैनबर थी। मैं उस वक्त की भी बात जानती हूँ। उस वक्त लैंड ऐलिनिये इन ऐक्ट की तरह के बिल आये जो कि जमींदार के लिए अच्छा था, गरीब के लिए वह चीज बड़ी अच्छी थी। उस वक्त हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी थी वह थी यूनियनिस्ट पार्टी। उस वक्त अंग्रेजों ने डिवाइड एण्ड रूल की पालिसी अपनाई हुई थी, सैप्रेट इलैक्टोरल रोलज थे, सिख—सिख को वोट दे सकता था, हिन्दू—हिन्दू को वोट दे सकता था और मुस्लमान—मुस्लमान को वोट दे सकता था और हिन्दुओं के अन्दर भी यह तमीज कि ऐग्रीकल्चरिस्ट अलग और नान—ऐग्रीकल्चरिस्ट अलग। नान—ऐग्रीकल्चरिस्ट का कोई आदमी जमीन नहीं खरीद सकता था। किसी का बच्चा फौज में भर्ती नहीं हो सकता था लेकिन इस हकूमत ने जाति—पाति की बात खत्म कर दी और अब हरेक आदमी का बच्चा, चाहे वह बनिया का बच्चा हो, हरिजन का बच्चा हो, वह अब फौज में जा सकता है। एक और चीज इस सरकार ने की है कि हरेक आदमी को अब जमीन खरीदने का

अधिकार है । हर आदमी अब जमींदार बन सकता है । अब कोई भी आदमी जाति से जमींदार नहीं बन सकता बल्कि पैसे से जमींदार बन सकता है । चाहे अब कोई भी जाति काहो अगर वह किसान का काम करता है तो वह जमींदार है । इस सरकार ने जो जात पात का भेद था वह बिल्कुल खत्म कर दिया । जनाब, अब मैं अपने हल्के की बात करूंगी । मेरा हल्का अम्बाला है जो जिले का हैडक्वार्टर है । किसी जमाने में सारे हरियाणा में जो हरियाणा के सात जिले थे, अब ता वे नौ-दस जिले हो गये हैं, यह जिला उनको डोमिनेट करता था । इस जिले के अन्दर कमि नरी थी और आज भी कमि नरी है । बड़े-2 अफसर थे । स्पीकर साहब, मुझे खुशी है कि इस सरकार ने, इस बंसी लाल की सरकार ने जिन जिलों के अन्दर पीने का मीठा पानी नहीं था, उनको मीठा पानी सप्लाई किया, मुझे इस बात का फख है और मैं फख से सर ऊंचा कर सकती हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं । लेकिन मैं बंसी लाल सरकार से यह रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस प्रकार एक माँ के दो-तीन बच्चे हैं और उनमें से दो बच्चे कमजोर हैं, तो ठीक है उनको ज्यादा दूध दें, ज्यादा विटामिन दें, उस ज्यादा खर्च करें लेकिन जनाब साथ ही मेरी यह रिक्वेस्ट भी है कि माँ को यह भी ख्याल रखना चाहीये कि जो बच्चा हश्ट-पुश्ट है, उसका भी ख्याल रखें ताकि वह कमजोर न हो जाये । इसलिये मेरी बंसी लाल सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि वह अम्बाला का भी ख्याल रखे । ठीक है, हमें मिलक प्लांट दिया है ट्रांसफार्मरज की फैक्ट्री दी है और छोटे-मोटे काम तो मैं जो मेरे जिले के आफिसरज हैं मुझे

उनसे कहने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पडती, वे आप ही पूरा कर देते है। मैं तो बडी खुाकिस्मत हूं इस मामले में। मैं तो उनसे कह देती हूं कि भई ठीक है अगर आप विटामिन्ज देते रहोगे तो स्वस्थ रहूंगी, अच्छी रहूंगी और विटामिन है मेरी सडक ठीक करवा दो, ट्यूबवैल नहीं है वो लगवा दो। छोटे-मोटै काम आप करते रहोगे तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जनाब अब मेरी मांग क्या है? सबसे पहला सवाल जनाब मेरा पानी का है। जब मैं बोल रही हूं, तो चीफ मिनिस्टर साहब यंहा नहीं है।.....(विधान)स्पीकर साहब, ये कहते है कि अम्बाला के लिये पानी की बात कह दी। पानी तो पहले से ज्यादा है और ट्यूबवैलज भी लग गये है। मैं तो यह कहूंगी कि कम से कम अम्बाला भाहर के लिये कोई बडी स्कीम चालू की जानी चाहिये जिस तरह से हम जमीदारों को ट्यूबवैलज के लिये बिजली देते है उसी प्रकार से अम्बाला भाहर के अन्दर भी , जहां कि लाखों लोग कहते रहते है, वहां के ट्यूबवैलज को भी ज्यादा बिजली मिलनी चाहिये जिससे कि भाहर के अन्दर पानी के लिये हाहाकार न मचे।

दूसरी चीज यह है कि घग्गर के उपर बांध लगाने से काफी पैसा खर्च आयेगा। इसके लिये तो मैं जोर नहीं देती। एक नरवाना ब्रांच है , जोकि हमारे अम्बाला से गुजर कर जाती है । उससे टिब्बों में पानी लिया गया थां क्या उससे थोडा सा पानी अम्बाला को नही दिया जा सकता? मैं रिक्वैस्ट करूंगी कि इस स्कीम के तहत अम्बाला के अन्दर पानी का प्रबन्ध भीघ्र ही किया

जाना चाहिए। एक और सीवरेज की स्कीम है जोकि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, मैंने वहां के ऐडमिनिस्ट्रेटर से भी बात की थी कि उस पर कितना पैसा लगेगा। उसने मुझे जवाब दिया कि कम से कम 70-80 लाख रुपया उस स्कीम पर लगेगा। मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने आपको इस काम के लिए कितना दिया है ? उन्होंने कहा कि 23 हजार रुपया ग्रान्ट दी है और 17 हजार रुपया लोन दिया है। आप ही बताइए कि किसी म्यूनिसिपल कमेटी ने अगर इतने बड़े काम को अपने हाथ में लिया हुआ हो तो उसका इतने पैसे के क्या बनेगा ? भायद हमारे मिनिस्टर साहब यह कहें कि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो इतनी बड़ी स्कीम को हाथ में क्यों ले लिया ? मैं आपको बताना चाहती हूं कि अम्बाला का नक्शा ऐसा है, अम्बाला को लेवल ऐसा है, सीधा कड़ाहा जैसा, चारों तरफ से पानी आ करके बीच में जमा हो जाता है। अगर हम उस को सीधा करने के लिये गौर नहीं करेंगे, तो हम उसका लेवल सीधा नहीं कर सकेंगे। इसका इलाज यह कि नालियां बनाकर पानी को बाहर निकालने की कोशिश की जाए। तो यहां इसके लिये सीवरेज स्कीम की ज्यादा जरूरत है। स्पीकर साहब, ज्यादा क्या कहूं, अकलमंद के लिये तो इलाज ही काफी है। हमारी तो मिनिस्टर साहब बड़े मेहरबान हैं। मुझे उनसे पूरी आशा है कि वे हमारे अम्बाला भाहर की इन डिफिकल्टीज की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि चण्डीगढ़ के बिल्कुल पास है और वहां की म्यूनिसिपल कमेटी को इस स्कीम के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा देंगे। इसके साथ साथ एक और चीज है कि वहां पर जो

नालियों है, वे सारी की सारी गल गई है और उन में से पानी लीक करता है। अगर उनको बदल दिया जाये, तो कई लाख रूपया लगेगा। इसके लिये भी मिनिस्टर साहब देखे, और कमेटी की ज्यादा मदद करे। यह बड़े दुःख की बात है कि आज आप जब गांव गांव में पानी दे रहे हो, टिब्बों में पानी दे रहे हो, तो यह हमारे हल्के के साथ ऐसी ज्यादाती क्यों हो रही है? अगर आप इस गवर्नमेंट के होते हुए यह काम पूरा न हुआ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हजारों सालों तक यह काम कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा।

स्पीकर साहब, मैंने कुछेक बातें सप्लीमेंट्री में पूछी थी। आर्डर होता है कि कभी कभी सप्लीमेंट्री कर लिया करें, कभी कभी हो भी जाती है, क्योंकि स्पीकर साहब, आपकी मेहरबानी से टाईम मिल भी जाता है। मैंने हस्पतालों के लिये भी ए सप्लीमेंट्री किया थां क्वै चन आवर में हमारी हैल्थ मिनिस्टर महोदया ने बताया कि अम्बाला की बिल्डिंग 25 साल पुरानी है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि अम्बाला की बिल्डिंग तो पता नहीं सौ साल या 80 साल या कितनी ही पुरानी होगी। एक बाद मैंने भी हैल्थ मिनिस्टर साहिबा से पूछा था, तो इन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिये अस्पताल की सोच रहे हैं। कौन सी जगह हो और कहां अनाया जाये, यह नहीं बताया, यह कह दिया कि जगह नहीं है। मैं तो यह कहती हूँ कि अम्बाला के बीच में अगर कोई ऐसा बड़ा हस्पताल होगा, तो दूर दूर से लोग वहां पर इलाज के लिये आएंगे, और इस तरह से

सरकार की वाह वाह होगी। लेकिन इस बात के ऊपर गौर नहीं किया गया। मैंने पता किया है, सरकार इस काम के लिये राज हो तो वहां पर 9 एकड़ के करीब जमीन, फ्री आफ कास्ट में दिलवाने के लिये तैयार हूं। उसकी लगभग 10 लाख कीमत होगी। इसलिये मेरी गुजारि है कि अम्बाला के अन्दर एक बड़ा अस्पताल बनना चाहिए। मैं इसके आगे आती हूं, एक ही बात के ऊपर जोर नहीं देती, सड़कें तो बन गई हैं, लेकिन एक सड़क है, जिसके बनाने के आर्डर तक हो गये, वह है जटियाना, वहां पर बजरी वगैरह भी गिरवा दी गई, मिट्टी वगैरह व दूसरा सारा सामान वहां पर पहुंच गया, (हंसी) पर अभी तक उस सड़क का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। अनाब, जिस वक्त इलैकान था, कुछ लोग मेरे पास आये। मुझे कहने लगे कि बहन जी, मानकपुर की सड़क एक गांव से जोड़ी जा रही है, जबकि जी.टी. रोड़ हमारे पास ही है। तो इसकी जरूरत क्या है जो सड़क मानकपुर से निकलने वाली ही है, वह ही जी.टी. रोड़ से मिला दो। तो उसी वक्त मैं वहां गई और ऐक्सीयन साहब को बुलाया और कहा कि इस सड़क के काम को फौरन बंद करो और उसी सड़क को जी.टी. रोड़ से मिलाओ। जनाब, मैंने काम बंद करवा दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आज तक वह सड़क ही नहीं बनी (हंसी)। अब सोचने की बात यह है कि उस का फिर वह रूपया कहां चला गया? यह गवर्नमेंट यह कह देती है कि हमारी पालिसी यह है कि कोई नई सड़क न बनाई जायें तो मेरी गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दिया जाये।

इसके बाद जनाब एक सड़क अम्बाला भाहर है। उसके लिये कमेटी ने पैसा भी जमा करवा दिया है। इसलिये उसको खास तौर से नोट कर ले। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की यह पालिसी होनी चाहिये जहां तक बड़ी सड़क की बजाय एक एक फर्लांग की दस सड़कें बनानी हो, तो पहले उन दस सड़कों को प्रैफ्रेंस दिया जाना चाहिए। उससे यह भी होगा कि आप गए गांव की बजाये दस गांवों को खुला कर सकते है। उसके बाद ट्यूबवैलों की बात है। ट्यूबवैल तो मेरे हल्के मे बिल्कुल ही कम मिले है। चट्ठा साहब यहां नही है। मैं उनको बताना चाहती थी कि उनके पहले हल्के के पांच गांव अब मेरे हलके मे है। मैंने उन पांच गांवों का दौरा किया तो उन्होंने मेरे पास ट्यूबवैलों का रोना रोया। मुझे यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि चट्ठा साहब के पहले इलाके मे भी ट्यूबवैलों की आवश्यकता हो रही है। तो मैंने आकर चट्ठा साहब को कहा कि वह आपका इलाका रहा है और आपको अपने पुराने आदमियों को याद रखना चाहिए इसलिये आप वहां पर जरूर ट्यूबवैल दो। ये गांव है टुंउला टुंडली वगैरह वगैरह। इसके अलावा और भी गांव है, जैसे खतौली मानकपुर और धूलकोट इनकी सड़कों की मुरम्मत होने वाली है। मानकपुर की जो सड़क है उसकी रोड़ी बाहर निकल आई है और वह इतनी खराब हो गई है कि अगर उसकी दो चार महीने तक और मुरम्मत न की गई तो वह सड़क दोबारा बनानी पड़ेगी। इसलिये मिनिस्टर साहब खास तौर पर इस चीज को नोट कर ले कि जिन सड़कों की मुरम्मत होने वाली है उनकी मुरम्मत करवा दी जाये, ताकि

उनको दोबारा न बनाना पड़े। इसी तरह एक धूलकोट की सड़क, वह भी बिल्कुल टूटी पड़ी है। उसकी भी अगर मुरम्मत करवा दी जाये तो वहां लोगों को भी सहूलियत मिल जायेगी और अभी आपका भी पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा। स्पीकर साहब, आज आपने मुझे बोलने का समय दिया इसलिये आज जब मैं एक लफज बोलती हूं तो दस बाद दिल से भुक्रिया का लफज निकलता है कि आपने कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दिया। इसके बाद मैं बसों की बात पर आती हूं। यहां पर किसी क्वै चन की जब सप्लीमेंट्री होती है तो मेरे अपोजी इन के भाई ट्रेजरी बेंचिज की तरफ इ पारे करके कहते हैं कि आपकी बसें खराब हैं, ठीक नहीं चलती हैं लेकिन जब कभी यही हमारे अपोजी इन के भाई प्रांत से बाहर किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं तो कहते हैं कि अगर कहीं काम हुआ है तो वह हरियाणा में हुआ है। सबसे अच्छा जो लीडर आफ दी हाउस में है तो वह बंसी लाल है। प्रताप सिंह कैरो के बाद अगर कोई चीफ मिनिस्टर आया है, तो वह बंसी लाल है मैं उनको बताना चाहती हूं कि इसमें कोई भाक नहीं है कि हमारे प्रांत में वाक्या ही बड़े भारी काम हुए हैं। हमारा लीडर लौह पुरुश है, लोहे का बना हुआ है। इसी तरह से हमारे कर्नल महा सिंह जी भी बड़े मेहनती और काम करने वाले व्यक्ति हैं। इस चीज को मैंने भी कहा था कि वाक्या ही हरियाणा की बसों के जो कन्डक्टर हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि यात्रियों के साथ कैसे विहेव करना चाहिए। कइ बार देखने में आया है कि वे इतने रूड हो जाते हैं कि कम्बखत इज्जत नहीं करते। कहते हैं, अरे उधर बैठ, खड़ा हो

जो, इस तरह की बातें कहते हैं। जनाब, मैं इन बातों में ज्यादा नहीं जाना चाहती। मैं तो अपना मतलब हल करना चाहती हूँ।

—(हंसी)— इसके बाद मैं अम्बाला भाहर के बस अड्डे के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि वह मेन रोड़ पर नहीं है, बल्कि भाहर के अंदर है। अम्बाला भाहर से कैंट जाने के लिये 20 मिनट लग जाते हैं। मेन रोड़ पर न होने के कारण वहाँ बसें कम जाती हैं। उसके मुकाबले में अम्बाला कैंट में बसें आधा आधा घंटा खड़ी रहती हैं। तो इसकी क्या जरूरत है? अम्बाला भाहर भी तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है और वहाँ लोगों का आना जाना बड़ा जरूरी है ? अम्बाला भाहर भी तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है और वहाँ लोगों का आना जाना बड़ा जरूरी है। एक व्यापारी या कोई दूसरा आदमी वहाँ से अगर सुबह चार बजे दिल्ली जाना चाहे तो उसको पहले अम्बाला कैंट तक तीन चार रूपये स्कूटर के खर्चने पड़ते हैं। तो हर आदमी तो स्कूटर या टैक्सी के पैसे खर्च कर नहीं सकता। इसीलिये इसका एक ही इलाज है कि जितनी भी बसें चण्डीगढ़ से दिल्ली जाती हैं कम से कम उनमें आधी अम्बाला भाहर में से हाकर जानी चाहिए। (घंटी) स्पीकर साहब, आप घंटी दे रहे हैं, इसलिये मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो सरपंच का चुनाव है, अगर वह डायरेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या हर्ज है? बातें तो कहने के लिये बहुत थी लेकिन समय न होने के कारण मैं आपका भुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और बाकी जो बातें रह गई हैं वे मैं कभी फिर कह दूंगी।

श्री राम सरन चंद मित्तल: स्पीकर साहब, मैंने जवाब जरूर देना था, लेकिन अब समय थोड़ा है इसलिये जिस दिन डिमांडज पर डिस्कान होगी उस दिन जवाब दे दूंगा।

श्री जगजीत सिंह टिक्का (नारायणगढ़): स्पीकर साहब, मैं आपका मकसूर हूँ, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज तो समय खत्म होने वाला है लेकिन उस दिन तो मुझे कंटीन्यू करने का मौका मिलेगा ही। मैं मित्तल साहब को मुबारिकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बजट पेश किया है वह एक ऐसा बजट है जिस पर अगर देखा जाये तो इसमें जो खर्च करना है वह ऐसी चीजों पर करना है जो कि हमारे हरियाणा की उन्नति के लिये है। मिसाल के तौर पर जैसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं इरीगेशन और पावर है तथा एग्रीकल्चर है। मेन खर्च जो आपका है वह इनमें आता है हमारा जो प्लान ऐक्सपेंडीचर है वह 83.74 करोड़ का है और उसमें से जो एग्रीकल्चर, पावर प्रोजेक्ट्स और इरीगेशन है, उन सब पर 57.45 करोड़ रूपया खर्चा होगा। तो इससे यह साबित होता है कि हमारी सरकार जनता का कितना खयाल रखती है। हमने लोगों को ऊपर उठाना है, हरियाणा को बढ़ाना है। हमारे भाई यहां पर चर्चा करते हैं कि क्योंकि यह बजट डैफिसिट बजट है, इसलिये यह कोई अच्छा बजट नहीं है। ठीक है इस बार का जो बजट है वह करीब 17 करोड़ के डैफिसिट का बजट है लेकिन अगर हम पिछले साल का बजट देखें तो पिछले साल का बजट इससे भी ज्यादा डैफिसिट का था यानी कि उस

बजट मे 17.97 करोड़ का डैफिसिट था लेकिन अब साल के अंत मे उसमे से जो हमारे पास डैफिसिट रह गया है वह है सिर्फ 6.33 करोड़। इसलिये हमें घबराना नही चाहिए कि हमारे बजट मे ज्यादा डैफिसिट है क्योंकि इससे पिछले साल भी यही हुआ था और यही बताया गया था कि 17-18 करोड़ का घाटा होना लेकिन अब साल के अखिर मे निकला सिर्फ 6.33 करोड़।

Mr. Speaker: The House stand adjourned till 2.00 p.m. on Monday.

13.00 बजे

(The Sabha then adjourned* till 2.00 p.m. on Monday, the 13 January, 1975).